कमल संदेश

'बच्चे नए भारत के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण हीरो'

वर्ष-12, अंक-22 16-30 नवम्बर, 2017 (पाक्षिक) ₹20

'गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान' का शुभारंभ

नव कर्नाटक निर्माण परिवर्तन रैली | हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर विशेष | कदम जिससे अर्थव्यवस्था बदल गई

गुजरात, हिमाचल तथा कर्नाटक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की रैलियों की छवियां

गांधीग्राम, गुजरात में कच्छ, मोरबी और सुरेंद्र नगर जिलों के भाजपा शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित करते श्री अमित शाह

नारनपुरा में 'हर दरवाजे पर' अभियान का शुभारंभ करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

सुरेंद्र नगर, गुजरात में जनाभिवादन स्वीकार करते श्री अमित शाह

गोधरा, गुजरात में रैली को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में आयोजित जनसभा को संबोधित करते श्री अमित शाह

हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में संपन्न रैली में उमड़ा जनज्वार

बंगलौर में 'नव कर्नाटक निर्माण परिवर्तन यात्रा' के शुभारंभ से पहले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का स्वागत करते कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेतागण

बंगलौर में 'नव कर्नाटक निर्माण परिवर्तन यात्रा' का शुभारंभ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा
कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी
सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह
कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोनः +91(11) 23381428
फैक्स
फैक्सः +91(11) 23387887
ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइटः www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 'गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान' शुरू

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 7 नवंबर को गुजरात में अहमदाबाद के नारनपुरा से 'गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान' की शुरुआत की। श्री शाह ने सोला रोड क्षेत्र में अंबाजी मंदिर में पूजा करने के बाद इस अभियान की शुरुआत नारनपुरा निर्वाचन क्षेत्र से की जहां से वह पूर्व में...

वैचारिकी

मैं और हम 16

श्रद्धांजलि

के. आर. मलकानी / गौहर अहमद भट 18

लेख

डिमोनेटाईजेशन के एक वर्ष 24
कदम जिससे अर्थव्यवस्था बदल गई 27

अन्य

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2 लाख 11 हजार करोड़ रुपये का पुनर्पूंजीकरण 14
कांग्रेस ने मैदान छोड़कर अपनी हार स्वीकार कर ली है : नरेन्द्र मोदी 18
कांग्रेस सरकार ने राज्य में विकास की सभी संभावनाओं को ख़त्म कर दिया हैः अमित शाह 22
सेल इस्पात से निर्मित एक्सप्रेस-वे पर वायु सेना का सुपर हरक्यूलिस विमान उतरा 28
मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ महंगाई भी काबू में 29
'बच्चे नए भारत के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण हीरो' 32

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04
पत्र-पत्रिकाओं से 33
स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

09 भाजपा ने जारी किया विजन डॉक्युमेंट

भाजपा ने अपने विजन डॉक्युमेंट (घोषणापत्र) को 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र' नाम दिया है...

10 'नव कर्नाटक निर्माण परिवर्तन रैली' को हरी झण्डी दिखाई गई

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने नव कर्नाटक निर्माण...

सरकार की उपलब्धियां

12 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में भारत की 30 पायदान की उछाल

केंद्र की मोदी सरकार के सुशासन और ऐतिहासिक आर्थिक सुधार लागू करने से भारत...

13 5 लाख 35 हजार करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने अधिक दक्ष परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने की अपनी...

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

2014 में जनता ने ऐसा शासन चुना जिसने तय किया है कि दिल्ली से जो पैसा निकलेगा, वो पूरा पैसा गरीब की सेवा में जाएगा।

@AmitShah

मोदी सरकार ने नोटबंदी से ना सिर्फ कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई बल्कि इससे वित्तीय प्रणाली को सुचारू कर मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी।

@arunjaitley

विमुद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने और व्यवस्था में काले धन का प्रवाह कम करना था।

facebook

आज समाज में समरसता की कमी होती जा रही है और ऐसे में समाज निर्माण का कार्य आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारी सरकार सभी जाति, धर्म और वर्ग से जुड़े लोगों को साथ लेकर पूरे प्रदेश को एकसूत्र में पिरोने का काम कर रही है। देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां धरोहरों के संरक्षण के लिए धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन किया गया है। हमारी सरकार ने इस कार्यकाल में 600 करोड़ से अधिक के मंदिर विकास व धरोहर संरक्षण के काम शुरू किए हैं।

—वसुंधरा राजे

नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर विराम लगा है। आम आदमी को राहत और काला बाजारी करने वालों को चोट पहुंची है। आम आदमी के लिए होम लोन सस्ता और जीवन सरल हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस क्रांतिकारी निर्णय से देश की विकास दर बढ़ी है। भारत अधिक समर्थ हुआ है।

— शिवराज सिंह चौहान

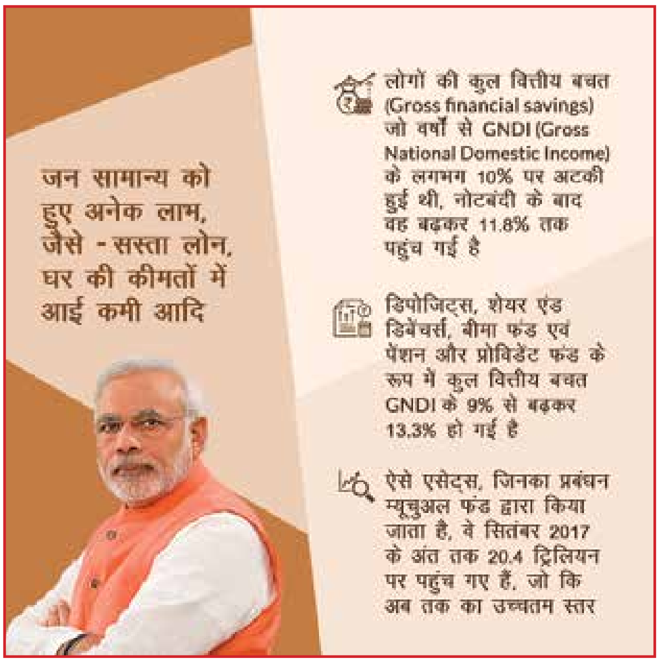

कालाधन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान विजय पथ पर अग्रसर

जैसे-जैसे 'रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म' के परिणाम चमत्कारिक रूप से सामने आते जा रहे हैं, कांग्रेसनीत विपक्ष के लिए केंद्र की भाजपानीत राजग सरकार की कोई तर्कपूर्ण आलोचना प्रस्तुत करना कठिन होता जा रहा है। कालाधन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाये जा रहे हर कदम का विरोध कर कांग्रेस ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह अपने अतीत से कोई सबक नहीं लेना चाहती। कांग्रेस को यह याद रखना चाहिए कि जनता ने उसे सत्ता से बाहर का रास्ता इसलिए भी दिखाया है कि उसने कालाधन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने से इंकार कर दिया था। इसके शासन में 12 लाख करोड़ से भी अधिक घपलों एवं घोटालों से भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई थी। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर कालाधन पर एसआईटी की जांच नहीं बिठाया तथा कालेधन के कारोबारियों को अपने लूटे हुए धन को ठिकाने लगाने का सुनहरा अवसर दिया। अब भी इसे नोटबंदी तथा जीएसटी का विरोध करने में कोई शर्म नहीं, जिससे भारत में साफ-सुथरी अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा रही है। इस सबका परिणाम देश में सकारात्मक वातावरण में देखा जा सकता है, जब सेंसेक्स रिकार्ड तोड़ छलांगें लगा रहा है। कांग्रेस तथा इसके सहयोगियों द्वारा 8 नवंबर, जब पिछले वर्ष इसी दिन प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, को 'काला दिवस' मनाने का ऐलान कर कालेधन के कारोबारियों तथा भ्रष्टाचारियों के प्रति अपना समर्थन खुलकर जता दिया है। इसकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए।

जबकि 8 नवंबर को पूरा देश 'कालाधन विरोधी दिवस' मना रहा है तब यह समझना भी आवश्यक है कि इस ऐतिहासिक कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है तथा पूरे विश्व का विश्वास अर्जित कर पाई है। एक ओर जबकि बाजार उठान पर है कई फर्जी कंपनियों को बंद किया जा चुका है और संदेहास्पद खातों की जांच की जा रही है। भारत अब 'लेस कैश इकोनॉमी' की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है तथा बैंक खातों में जमा धन अब व्यवस्था के प्रति जवाबदेह है। इससे देश के कर-आधार में जो व्यापक वृद्धि दर्ज हुई है वह अद्भुत है। करदाताओं की संख्या में भी जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। आतंकवाद-नक्सलवाद-माओवाद तत्वों के संसाधनों को भी गहरा धक्का लगा है, जो उनके गतिविधियों में भारी गिरावट से समझा जा सकता है। देश में बैंक ब्याज में जो कमी हुई है उससे देश के एक बड़े वर्ग को सीधा लाभ मिल रहा है। 'रियल स्टेट' बाजार जिसे काला धन खपाने का एक बड़ा माध्यम भ्रष्टाचारियों के द्वारा बना दिया गया था तथा जिस सेक्टर में कीमतें आसमान छू रही थीं, अब उस पर लगाम लग चुकी है तथा एक आम आदमी भी अपने लिए घर का सपना पूरा कर सकता है। एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन गिनाया जा सकता है वह है भारत की साफ-सुथरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होना तथा 'सब चलता है' की मानसिकता से निकलकर 'हो सकता है' की प्रवृत्ति का उदय होना है। इससे विश्व में भारत का कद बहुत ही बढ़ा है तथा भारत अब सम्मान के साथ देखा जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अब अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप, पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाने लगा है। कई प्रकार के संशय और आलोचना को पार करते हुए 'नोटबंदी' ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक परिदृश्य में उभरने का आधार तैयार कर दिया है।

> कालाधन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जबरदस्त युद्ध छेड़कर प्रधानमंत्री ने देश के राजनैतिक नेतृत्व पर लोगों का विश्वास पुनः जगा दिया है तथा पूरे विश्व में भारत के उदय के प्रति अब लोग आश्वस्त दिख रहे हैं। कांग्रेस का बार-बार खोखले नारे लगाना अब उसे महंगा पड़ रहा है तथा उसका आधार अब काफी हद तक सिकुड़ चुका है।

एक ओर जहां नोटबंदी और जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव अब महसूस किया जाने लगा है, 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' की सूची में भारत ने 30 स्थानों की छलांग लगाकर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि अभी 'नोटबंदी एवं जीएसटी' जैसे हाल के बड़े सुधारों को इस सर्वे में शामिल नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद से भारत इस तालिका में लगातार अपने स्थान का सुधार करता जा रहा था तथा पूर्व के वर्षों में 142 से 130 तक की यात्रा हो चुकी थी। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत एवं दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति के कारण 130 से 100 तक की छलांग को समीक्षक असाधारण उपलब्धि मान रहे हैं। कालाधन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जबरदस्त युद्ध छेड़कर प्रधानमंत्री ने देश के राजनैतिक नेतृत्व पर लोगों का विश्वास पुनः जगा दिया है तथा पूरे विश्व में भारत के उदय के प्रति अब लोग आश्वस्त दिख रहे हैं। कांग्रेस का बार-बार खोखले नारे लगाना अब उसे महंगा पड़ रहा है तथा उसका आधार अब काफी हद तक सिकुड़ चुका है। 2014 में किसी भी समीक्षक के लिये यह कहना कठिन था कि मात्र साढ़े तीन वर्षों में देश वापस पटरी पर आ जाएगा तथा कांग्रेस का इतना भयानक पतन होगा। आज जबकि सुधारों का विरोध करने वालों को जनता चुनाव-दर-चुनाव सबक सिखा रही है, प्रधानमंत्री द्वारा कालाधन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान निरंतर विजयपथ पर अग्रसर हैं। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

'गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान' शुरू

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 7 नवंबर को गुजरात में अहमदाबाद के नारनपुरा से 'गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान' की शुरुआत की। श्री शाह ने सोला रोड क्षेत्र में अंबाजी मंदिर में पूजा करने के बाद इस अभियान की शुरुआत नारनपुरा निर्वाचन क्षेत्र से की जहां से वह पूर्व में विधायक रह चुके हैं। प्रचार अभियान के तहत उन्होंने करीब 10 आवासीय सोसायटियों का दौरा किया। ढोल-नगाड़ों के बीच उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ निवासियों से बातचीत की, कुछ घरों में गए, लोगों का हाल-चाल पूछा और उनसे आगामी चुनाव में भाजपा को वोट देने का निवेदन किया।

नर्मदा यात्रा व गुजरात गौरव यात्रा के बाद भाजपा का यह तीसरा बड़ा चुनावी अभियान है। श्री अमित शाह के अलावा राज्य व केंद्र के दो दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेता व मंत्री इस अभियान से जुड़कर घर-घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचा रहे हैं। घर-घर जाकर प्रचार करने के इस तरीके के माध्यम से पार्टी ने राज्य के 50 हजार मतदान केंद्रों के तहत मत डालने वाले लोगों तक पहुंचने की योजना बनाई है।

गुजरात की जनता को केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए 6 दिवसीय गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान शुरू किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उपमुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री प्रकाश जावडेकर, श्री जेपी नड्डा, श्री वीके सिंह, श्री जितेंद्र सिंह, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री थावर चंद गहलोत, श्री मनसुख मांडविया, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्री पीपी चौधरी, श्री पुरुषोत्तम रूपाला सहित राज्य व केंद्र के एक दर्जन से अधिक पार्टी नेताओं ने इस महाअभियान में हिस्सा लिया।

श्री अमित शाह ने महासंपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करने को कहा। इसके बाद सूरत भाजपा के नेता वार्ड लेवल पर घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की। सूरत की सभी 16 विधानसभा क्षेत्रों में सांसद, विधायक, टिकट के दावेदार, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों के घर गए। शहर भाजपा प्रमुख श्री नितिन भजियावाला ने सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक रणजीत गिलितवाला के साथ डोर टू डोर संपर्क किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में इस महासंपर्क अभियान में सूरत के स्थानीय नेता ही नहीं, प्रदेश और केंद्र के नेता भी भाग लेंगे। भाजपा के महासंपर्क अभियान के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है। शहर प्रमुख श्री नितिन भजिया वाला ने पूर्व विधानसभा क्षेत्र में प्रचार की कमान संभाली, वहीं सांसद दर्शना जरदोष ने कतारगाम में डोर टू डोर प्रचार किया। कतारगाम के विधायक और मंत्री नानू वानाणी ने सूरत उत्तर में और पाटीदार बहुल वराछा में उत्तर विधानसभा के विधायक अजय चोकसी ने अभियान की अगुआई की। सूरत पश्चिम में प्रचार की कमान मेयर अश्मिता शिरोया के हाथ थी। लिंबायत में भाजपा के कनु जोशी, चौर्यासी में एपीएमसी के चेयरमैन रमन जानी और कामरेज से डिप्टी मेयर शंकर चेवली की अगुआई में संपर्क किया गया। ■

> @AmitShah
> नारनपुरा से गुजरात गौरव संपर्क अभियान का शुभारंभ किया और घर-घर जाकर मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की उपलब्धियां बताई।

कांग्रेस के लिए विकास एक मजाक है जबकि भाजपा के लिए मिज़ाज: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 नवंबर को कच्छ के सिंधु भवन, गांधीधाम में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और गुजरात के विकास का मजाक उड़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुजरात की जनता का अपार स्नेह एवं आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिलता आया है, उसी तरह इस बार भी जनता का प्यार भाजपा को मिलेगा और पार्टी 150 से अधिक सीटें जीतकर तीन-चौथाई की बहुमत से गुजरात में सरकार बनायेगी।

कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी विकास का मजाक उड़ाते हैं, मैं राहुल गांधी को विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए विकास एक मजाक है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास मिज़ाज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष विकास का मजाक उड़ाते हैं जबकि विकास करना हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के वक्त तो दिखाई देती है, लेकिन चुनाव के बाद पता ही नहीं चलता कि वह कहां गायब हो जाती है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में आकर गुजरात के विकास का मजाक उड़ाते हैं और झूठे आंकड़े देते हैं, लेकिन गुजरात की जनता राहुल गांधी से पांच प्रश्न पूछना चाहती है, इन प्रश्नों का

गुजरात की जनता राहुल गांधी से यह जानना चाहती है कि नर्मदा योजना को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने लटका कर क्यों रखा, कांग्रेस सरकार ने नर्मदा डैम के दरवाजे लगाने और बंद करने की मंजूरी क्यों नहीं दी, कांग्रेसी सरकारों ने कच्छ को रेगिस्तान की स्पेशल ग्रांट क्यों नहीं दी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर को केंद्र की यूपीए सरकार का ग्रांट क्यों नहीं मिला और गुजरात को क्रूड ऑयल की रॉयल्टी ग्रांट देने में कांग्रेस ने वर्षों तक अन्याय क्यों किया?

जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता राहुल गांधी से यह जानना चाहती है कि नर्मदा योजना को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने लटका कर क्यों रखा, कांग्रेस सरकार ने नर्मदा

डैम के दरवाजे लगाने और बंद करने की मंजूरी क्यों नहीं दी, कांग्रेसी सरकारों ने कच्छ को रेगिस्तान की स्पेशल ग्रांट क्यों नहीं दी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर को केंद्र की यूपीए सरकार का ग्रांट क्यों नहीं मिला और गुजरात को क्रूड ऑयल की रॉयल्टी ग्रांट देने में कांग्रेस ने वर्षों तक अन्याय क्यों किया?

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 1995 से लेकर 2017 तक गुजरात में हुए सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के आशीर्वाद और प्यार के लिए उनकी ऋणी और आभारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश में हुए लगभग हर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और कांग्रेस हारी है। इस बार भी गुजरात में कांग्रेस की हार निश्चित है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2001 से 2014 का भाजपा सरकार का कार्यकाल गुजरात का स्वर्णिम काल रहा है। साथ ही गुजरात के गौरव एवं विकास की यह परंपरा श्रीमती आनंदीबेन पटेल और श्री विजयभाई रुपानी एवं श्री नितिन पटेल के नेतृत्व में आगे बढ़ी है।

कांग्रेस पर विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक देश को विकास से महरूम रखने और देश की प्रगति को अवरोधित करने वाली गरीब विरोधी कांग्रेस देश व दुनिया के ग्रोथ इंजन गुजरात में आकर गुजरात के विकास पर सवाल खड़े करती है, तब गुजरात की जनता राहुल गांधी से प्रश्न पूछना चाहती है कि आपने आजादी से अब तक गुजरात और देश के विकास के लिए क्या किया?

राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जो अपने परिवार की परंपरागत लोक सभा सीट अमेठी और रायबरेली

का विकास तक नहीं कर पाए, उनसे विकास की आशा ही नहीं की जा सकती।

श्री शाह ने कहा कि आजादी से लेकर 1995 तक के कांग्रेस के कुशासन और 1995 से 2017 तक के भारतीय जनता पार्टी के शासन के फलस्वरूप गुजरात की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में गुजरात अंधेरे में जीने को विवश था, जबकि भाजपा के समय गुजरात में 24 घंटे बिजली आ रही है, कांग्रेस के समय शिक्षा के प्रति उदासीनता थी, जबकि भाजपा के समय समृद्ध शिक्षण नीति है, कांग्रेस की सरकार में गुजरात में सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। आज गुजरात में रोड सहित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की प्रतीक थी, जबकि भाजपा सरकार पारदर्शिता और विकास की प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के गुजरात शासन की तुलना करने पर पता चलता है कि चाहे वह बजट हो, कैपिटल इनकम हो, बिजली का उत्पादन हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, दुग्ध उत्पादन हो - हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की तुलना में कई गुना अधिक विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने हमने श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात में विकास की नई कहानी लिखी है। कर्फ्यू-मुक्त

गुजरात बनाने का काम श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि वाईब्रैंट गुजरात के माध्यम से राज्य में उद्योग और इन्वेस्टमेंट लाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने 1995 से पहले और 1995 से अब तक की स्थिति की तुलनात्मक रिपोर्ट पेश करते हुए विभिन्न विषयों पर विकास के आंकड़े प्रस्तुत किये जो इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।

कच्छ के विकास की चर्चा करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कच्छ देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला जिला है। उन्होंने कहा कि कच्छ में आये भीषण प्राकृतिक आपदा भूकंप के बाद गुजरात की मोदी सरकार एवं केंद्र की तत्कालीन भाजपा सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर हम कच्छ को पुनः विकसित करने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कच्छ का कायापलट हो चुका है, कच्छ आज प्रवासी लोगों के लिए आकर्षण के प्रमुख केंद्र के साथ-साथ औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को विकास दिखता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें विकास से कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल जब भी गुजरात में आयें तो विकास के आंकड़ों का अच्छे तरीके से अध्ययन करके आयें, वे गलत आंकड़े देकर गुजरात की जनता को गुमराह न करें और झूठ न फैलाएं। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी कांग्रेस के 60 वर्षों के शासनकाल और केंद्र की मोदी सरकार के तीन साल की उपलब्धियों का भी आकलन कर लें, तो भी उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि शेयर इन सेन्ट्रल टैक्स, ग्रांट इन ऐड, डिजास्टर रिलीफ, लोकल बॉडीज ग्रांट आदि को मिला दिया जाय तो 13वें वित्त आयोग में केंद्र की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने गुजरात को जहां केवल 63,346 करोड़ रुपए दिए थे, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात को 1,58,377 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने गुजरात को स्मार्ट सिटी के लिए 507 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 484 करोड़, अहमदाबाद मेट्रो के लिए 10,777 करोड़, यात्रा धाम विकास के लिए 22 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 532 करोड़, अमृत मिशन के लिए 267 करोड़, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए 128 करोड़, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के लिए 117 करोड़, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 255 करोड़, कच्छ हैंडीक्राफ्ट मेगा फेस्टिवल के लिए 28 करोड़, उदय डिस्कॉम योजना के लिए 6,800 करोड़ और मुद्रा बैंक योजना में 25 लाख लाभार्थियों को लगभग 16,110 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि गुजरात में 1,200 किमी नए नेशनल हाइवे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जहां गुजरात में 21,475 किमी सड़क के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, वहीं हमने लगभग 36,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य कराया। उन्होंने कहा कि CRCS योजना के तहत 48 हजार नए मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 6,53,695 हेक्टेयर जमीन को सिंचित क्षेत्र में लाने की मंजूरी दी गई, इसके साथ ही, राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एम्स, मेट्रो और मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की सौगात गुजरात को दी गई। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने घोघा-दहेज रोरो फेरी सेवा की शुरुआत की है जो विकास को और गति प्रदान करेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात की जनता कांग्रेस के प्रपंच से भलीभांति परिचित है, वह आने वाले चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को माकूल जवाब देगी। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भाजपा राज्य और राज्य की जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ■

भाजपा ने जारी किया विजन डॉक्युमेंट

भाजपा ने अपने विजन डॉक्युमेंट (घोषणापत्र) को 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र' नाम दिया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए कदम उठाने का वादा किया है। पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास करने के लिए कई योजनाएं लागू करने की बात इस पत्र में कही गई है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 29 अक्टूबर को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने शिमला में यह घोषणापत्र जारी किया। इसमें राज्य की जनता को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने के वादे के अलावा भ्रष्टाचार और माफिया राज को खत्म करने का वादा किया गया है। श्री जेटली के साथ इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल भी उपस्थित थे।

भाजपा ने अपने विजन डॉक्युमेंट (घोषणापत्र) को 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र' नाम दिया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए कदम उठाने का वादा किया है। पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास करने के लिए कई योजनाएं लागू करने की बात इस पत्र में कही गई है।

पत्र में सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई सुविधाएं देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में होशियार हेल्पलाइन, चोरी, नशे की रोकथाम के लिए मेजर सोमनाथ वाहिनी का गठन करने की योजना बनाई गई है। अवैध खनन से निपटने के लिए उच्च स्तरीय जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध पारदर्शिता स्थापित करने का पार्टी ने वादा करते हुए घोषणापत्र में कहा है कि भाजपा के विधायक सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति घोषित करेंगे।

भाजपा ने पीने के साफ पानी, सड़क-निर्माण और आपातकालीन स्थितियों के लिए हेलि-ऐंबुलेंस की सेवा शुरू करने की घोषणा पत्र में की गई है। वहीं रोजगार के क्षेत्र में ग्रेड 3 और 4 की नौकरियों के लिए साक्षात्कार बंद कर योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की बात कही गई है। कॉलेज के छात्रों के लिए लैपटॉप, टैबलेट, वाई-वाई और नौकरी दिलाने के लिए वार्षिक मेले लगाने का वादा किया गया है। बीपीएल परिवारों के छात्रों को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात भी कही गई है।

- न भ्रष्टाचार, न माफिया राज, सुशासन हो
- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जोर
- किसानों की आय दोगुनी करने का वादा
- पर्यटन को विशेष बढ़ावा
- महिला सशक्तिकरण पर भी नजर
- गरीबों के सिर पर छत का वादा

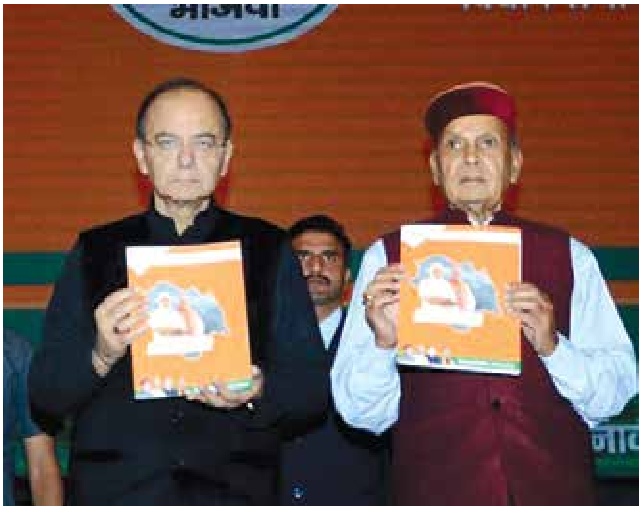

भाजपा ने साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया है। सब्सिडी बढ़ाई जाएगी और उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। भूमि अधिग्रहित करने पर सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा 4 गुना कर दिया जाएगा। एक बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा भी की गई है।

पर्यटन की दृष्टि से राज्य को लाभ दिलाने के लिए नए पर्यटन स्थलों के विकास की योजना पार्टी ने बनाई है। प्रचलन में आ रहे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए गांवों में होम-स्टे खोले जाएंगे। धार्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए भी कोष स्थापित करने की घोषणा की गई है।

महिला सुरक्षा के लिए गुड़िया योजना के तहत महिला पुलिस थाने और हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए सशक्त स्त्री केंद्र भी हर पंचायत में बनाए जाएंगे।

भाजपा ने अपना घर योजना के तहत 2022 तक हर गरीब को घर देने का वादा किया है। मजदूरों को अधिक न्यूनतम दिहाड़ी देने और असंगठित श्रमिकों को अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन देने की बात भी कही गई है। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिखाई 'नव कर्नाटक निर्माण परिवर्तन रैली' को हरी झण्डी

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार सर्वाधिक भ्रष्ट

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 2 नवंबर को नव कर्नाटक निर्माण परिवर्तन रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह 75 दिवसीय रैली है जो भाजपा कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष श्री बी. एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व में संचालित की गई है।

2018 में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा प्रचार की शुरुआत करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि यह परिवर्तन रैली मुख्यमंत्री को बदलने की नहीं है, न ही सरकार बदलने की है, न ही विधायकों को बदलने की है, बल्कि यह कर्नाटक प्रदेश को बदलने की है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों और युवाओं की किस्मत बदलने का है, इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था की स्थिति और राज्य में लोकायुक्त को शक्तिविहीन बनाना है, जो कांग्रेस सरकार के अधीन दुर्गति की स्थिति में पहुंच गई है।

कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह देश

यह परिवर्तन रैली मुख्यमंत्री को बदलने की नहीं है, न ही सरकार बदलने की है, न ही विधायकों को बदलने की है, बल्कि यह कर्नाटक प्रदेश को बदलने की है। इसका उद्देश्य किसानों और युवाओं की किस्मत बदलने का है, इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है, जो कांग्रेस सरकार के अधीन दुर्गति की स्थिति में पहुंच गई है।

जहां कहीं भी भाजपा सत्ता में है, चाहे वह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश या झारखंड हो, वहां इसने शानदार शासन प्रस्तुत किया है और विकास के लिए कार्य किया है। कर्नाटक कोई पिछड़ा राज्य नहीं है, परन्तु पिछले पांच वर्षों में यहां का विकास ठप्प पड़ गया है। केन्द्र का भेजा पूरा धन लूट लिया गया है।

की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है और उन्होंने कहा कि यह रैली कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में सिद्धारमैय्या की कमियों, उनके भारी भ्रष्टाचार तथा कुशासन को उजागर करेगी।

उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी भाजपा सत्ता में है, चाहे वह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश या झारखंड हो, वहां इसने शानदार शासन प्रस्तुत किया है और विकास के लिए कार्य किया है। कर्नाटक कोई पिछड़ा राज्य नहीं है, परन्तु पिछले पांच वर्षों में यहां का विकास ठप्प पड़ गया है। केन्द्र का भेजा पूरा धन लूट लिया गया है।

सिद्धारमैय्या सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकार्ड स्थापित कर दिया है और लोगों को लूटा गया है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैय्या सरकार का ज्यादा समय 18वीं शताब्दी के मैसूर शासक टीपू सुलतान को 1 नवम्बर के दिन मनाने में अधिक बीत रहा है। श्री शाह ने कहा कि टीपू जयन्ती समारोह मना कर वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा राज्य को कांग्रेस से छुटकारा दिलाने की उम्मीद से यात्रा में सहभागी हो रहे हैं।

केन्द्र में मोदी सरकार के सत्ता में रहते हुए, अगर कर्नाटक में भाजपा सरकार रहती है तो हम विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा विजन कृषि क्षेत्र की रक्षा करना है और किसानों का जीवन-यापन करना है। किसानों की आय दुगुनी होनी चाहिए, प्रत्येक गांव में 24 घंटे जलापूर्ति होनी चाहिए। यह हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री अमित शाह का विजन रहा है। हम कर्नाटक को मॉडल राज्य बनाकर रहेंगे।

श्री येदियुरप्पा ने कहा कि रैली में अन्य वरिष्ठ राज्य और केन्द्रीय नेता भी भाग लेंगे। यह रैली बंगलौर से 2 नवम्बर 2017 को शुरू होगी और 28 जनवरी 2018 को राजधानी में वापस लौटने से पूर्व सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों में भी पहुंचेगी।

श्री येदियुरप्पा ने कहा कि कम से कम प्रत्येक बूथ से इस बड़ी रैली में तिपहिया वाहन शामिल होंगे, परन्तु पार्टी का इस प्रकार की रैली की अनुमति नहीं मिली है और न ही बंगलौर से लगभग 250 कि.मी. कोडागु जिले से पास करने की इजाजत मिल पाई है, जैसा कि पहले मूल यात्रा पथ में शामिल किया गया था।

नगर में लाखों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक बंगलौर की बाइक रैली में शामिल होने के लिए जमा हो गए हैं।

बंगलौर से लगभग 60 कि.मी. दूर चन्नपटना से विधानसभा के एक विद्रोही कांग्रेस सदस्य और कुडाची के स्वतंत्र विधायक ने श्री अमित शाह की उपस्थिति में रैली में श्री पी. राजीव ने भाजपा में शामिल हो गए।

अन्य नेताओं के अलावा कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष श्री बी. एस. येदियुरप्पा, केन्द्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, श्री अनन्त कुमार, श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा, श्री रमेश जिगजंगी, श्री ए.के. हेगड़े, श्री जगदीश शेट्टार, श्री के ईश्वरप्पा और श्री ए.आर. अशोक भी इस रैली में भाषण दिए। ■

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में भारत की 30 पायदान की उछाल

देश पहली बार 100वें नंबर पर

केंद्र की मोदी सरकार के सुशासन और ऐतिहासिक आर्थिक सुधार लागू करने से भारत पहली बार विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में 100वें नंबर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि कारोबारी सुगमता के मामले में पिछले साल भारत 130वें नंबर पर था। एक साल में देश की रैंकिंग में अभूतपूर्व 30 अंक का उछाल आया है। खास बात यह है कि विश्व बैंक ने भारत को इस साल सबसे ज्यादा सुधार करने वाले दुनिया के शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल किया है। भारत इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया और ब्रिक्स समूह का इकलौता देश है। सच तो यह कि विश्व बैंक की ताजा रैंकिंग, विकास की बीते तीन साल की कहानी को बयान करती है। यह रिपोर्ट 31 अक्टूबर को वाशिंगटन में जारी की गई।

चहुंमुखी और विविध क्षेत्रों में सुधार का परिणाम है यह छलांग: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व बैंक की बिजनेस रिपोर्ट 2018 में भारत की 30 अंक की ऐतिहासिक छलांग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने रैंकिंग में इस सुधार को ऐतिहासिक की संज्ञा देते हुए कहा कि यह छलांग टीम इंडिया के चहुंमुखी और विविध क्षेत्रों में सुधार का परिणाम है। इस सरल कारोबारी वातावरण के चलते हमारे उद्यमियों, विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर उपलब्ध है और ये कही ज्यादा समृद्धि ला रहे है। पिछले तीन वर्षों में राज्यों के बीच व्यवसाय को सरल बनाने की सकारात्मक प्रतिस्पर्धा देखने में आई है। यह स्थिति लाभदायक रही है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में कारोबार करना कभी आसान नही रहा है। भारत दुनिया को आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के मंत्र से मार्गदर्शित होकर हम अपनी रैंकिंग में और सुधार और बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास करने के लिए दृढ़ निश्चय रखते हैं।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि रैंकिंग में यह उछाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असाधारण गति से हुए आर्थिक सुधारों का ही परिणाम है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि रैंकिंग में सुधार का श्रेय पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। यह साबित करता है कि किस तरह विभिन्न सुधारों और जनता के जीवन स्तर में बेहतरी की प्रधानमंत्री की नीति कारगर है।

दस मापदंडों में से छह पर भारत की रैंकिंग में भारी सुधार

विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस-2018' रिपोर्ट में दस मापदंडों के आधार पर सभी देशों को कारोबारी सुगमता के मामले में रैंकिंग दी गई है। दस मापदंडों में से छह पर भारत की रैंकिंग में सुधार आया है। माइनॉरिटी शेयरधारकों की सुरक्षा के मामले में भारत दुनिया भर में टॉप-5 में शुमार है। इस पैमाने पर देश की रैंक चार है, जबकि पिछले साल 13 थी। आसानी से कर्ज प्राप्त करने और बिजली कनेक्शन मिलने के मामले में भारत दुनिया के 30 शीर्ष देशों में शामिल है। कर्ज पाने के मामले में देश की रैंकिंग पिछले साल के 44वें नंबर से सुधरकर इस साल 29 हो गई है। टैक्स भुगतान के मामले में पिछले साल देश की रैंकिंग 172 थी, जो अब 119 हो गई है। दिवालियापन के मामले सुलझाने में रैंकिंग 136वें स्थान से 103 पर पहुंच गई है। मोदी सरकार ने संसद में अटके बैंक्रप्सी विधेयक को पारित कराकर लागू किया है। नतीजतन इस मापदंड पर देश की स्थिति में सुधार आया है। ■

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की मुख्य बातें

- **छोटे शेयरधारकों की सुरक्षाः** छोटे शेयरधारकों की सुरक्षा में भारत की रैंकिंग चौथे स्थान पर पहुंच गई है।
- **क्रेडिट मिलनेः** बिजनस के लिए क्रेडिट मिलने के मामले में भारत 29वें स्थान पर है।
- **प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीः** बिजनस के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के मामले की रैंकिंग में भारत 29वें स्थान पर है।
- **रिजॉल्विंग इनसॉल्वंसीः** इस मामले मे भारत 33 स्थान की छलांग लगाकर भारत 103 पर पहुंच गया है।
- **टैक्स भुगतानः** टैक्स भुगतान के मामले में पिछले साल देश की रैंकिंग 172 थी, जो अब 119 हो गई है।
- **नया बिजनस शुरू करनाः** नया बिजनस को शुरू करने मामले में भारत 156 स्थान पर पहुंच गया है। इसमें भारत की रैंकिंग में पहले के मुकाबले सुधार हुआ है।

5 लाख 35 हजार करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने अधिक दक्ष परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए न केवल सड़क सेक्टर के अवरोधों को समाप्त किया, बल्कि राजमार्ग विकास एवं सड़क निर्माण कार्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा भी दिया है। देशभर में माल और लोगों के आवागमन की सुगमता को और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार एक नए अम्ब्रैला कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। 83,677 किलोमीटर की सड़कों के लिए, इस सड़क निर्माण कार्यक्रम में अगले 05 वर्षों में 6.92 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय शामिल है। इसमें से, 5,35,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से क्रियान्वित की जाने वाली भारतमाला परियोजना से रोजगार के 14.2 करोड़ श्रमदिवसों का सृजन होगा।

बीएमपी के अधीन सड़कों (34,800 किलोमीटर) की निम्नलिखित श्रेणियां प्रस्तावित की गई हैं:

- आर्थिक कॉरिडोर (9000 किलोमीटर)
- अंतर कॉरिडोर और फीडर मार्ग (6000 किलोमीटर)
- राष्ट्रीय कॉरिडोर क्षमता सुधार (5000 किलोमीटर)
- सीमा सड़क और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी (2000 किलोमीटर)
- तटीय सड़क और पत्तन कनेक्टिविटी (2000 किलोमीटर)
- ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे (800 किलोमीटर)
- शेष एनएचडीपी निर्माण कार्य (10,000 किलोमीटर)

83,677 किलोमीटर की सड़कों के लिए, इस सड़क निर्माण कार्यक्रम में अगले 05 वर्षों में 6.92 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय शामिल है। इसमें से, 5,35,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से क्रियान्वित की जाने वाली भारतमाला परियोजना से रोजगार के 14.2 करोड़ श्रमदिवसों का सृजन होगा।

भारतमाला निर्माण कार्य, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, एमओआरटीएच और राज्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 05 वर्षों में 2021-22 तक संपन्न किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, ताकि तीव्र कार्यान्वयन को समर्थ बनाया जा सके।

गौरतलब है कि बाजार से ऋण के रूप में 2.09 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, पीपीपी के माध्यम से 1.06 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) की प्राप्तियों, टीओटी मुद्रीकरण अधिप्राप्तियों तथा एनएचएआई के टोल संग्रहण से 2.19 लाख करोड़ रुपए दिए जाने हैं।

भारतमाला के अधीन 34,800 किलोमीटर के अतिरिक्त, अन्य चालू स्कीमों के अधीन निर्माण कार्यों में से 48,877 किलोमीटर के शेष निर्माण कार्य का कार्यान्वयन 1.57 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से एनएचएआई/एमओआरटीएच द्वारा साथ-साथ किया जाएगा। इस का वित्तपोषण सीआरएफ से 0.97 लाख करोड़ रुपए और सकल बजटीय सहायता के रूप में 0.59 लाख करोड़ रुपए प्रदान करके किया जाएगा।

टीओटी मुद्रीकरण

पहली बार, एक न्यून जोखिम टोल – प्रचालन – अनुरक्षण – अंतरण (टीओटी) मॉडल के अधीन 82 कार्यरत राजमार्गों का मुद्रीकरण 34,000 करोड़ रुपए के निजी संभावित निवेश के साथ प्रारंभ किया गया है। एनएचएआई द्वारा 6258 करोड़ रुपए की संभावित मुद्रीकरण कीमत वाले 64 किलोमीटर के 09 एनएच खंडों के पहले बंडल के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। ■

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2 लाख 11 हजार करोड़ रुपये का पुनर्पूंजीकरण

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आरंभिक निवेश हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के पूंजीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है, ताकि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की राशि में वृद्धि हो और अधिकाधिक रोजगार सृजन हो सके। 24 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसके लिए चालू वर्ष में अधिकतम आवंटन तथा आगामी दो वर्षों के दौरान लगभग 2,11,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाएगा, जिसके लिए 18,139 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान, लगभग 1,35,000 करोड़ रुपये का पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करने तथा शेष राशि के लिए बैंकों द्वारा बाजार से पूंजी जुटाने और सरकारी इक्विटी को भुनाकर (लगभग 58,000 करोड़ रुपये संभावित) धनराशि जुटाने की आवश्यकता है।

सरकार का कार्य केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण तक ही सीमित नहीं है। पूंजीकरण के साथ ही उन्हें वित्तीय प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के लिए सुनिश्चित कदम उठाए जाएंगे। जिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैंकिंग क्षेत्र में 70 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है, उन्हें और अधिक विकास करने के लिए और बर्धित ऋण की राशि को उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस दिशा में देशभर में 'मुद्रा प्रोत्साहन' का अभियान चलाकर काम शुरू कर दिया गया है।

बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की मुख्य बातें

- **सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अभूतपूर्व मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध**
- **लंबे समय से चली आ रही अनर्जक आस्तियों को समाप्त करने के लिए बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु 2,11,000 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी**
- **पुनर्पूंजीकृत बैंकों के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए बैंकों द्वारा ऋण में वृद्धि**
- **बैंक रोजगार सृजन और विकास कार्यों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी राशि कर्ज देंगे**

वित्तपोषण और बाजार तक पहुंच में वृद्धि करके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास पर व्यापक बल दिया जाएगा तथा 50 कलस्टरों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तपोषित करने का अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों द्वारा नेतृत्व किया जाएगा एवं अभियान को गति प्रदान की जाएगी। ऋण के लिए किए गए आवेदनों पर बैंकों द्वारा निर्बाध रूप में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मूल्यांकन प्रक्रिया को कम करने और सही ऋण आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए फिनटेक कंपनियों (वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों) से सहायता ली जाएगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निम्नलिखित के माध्यम से सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाएगा।

- नकदी चक्र को कम करने के लिए बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 90 दिनों के भीतर व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रानिक छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) पंजीकरण को अनिवार्य बनाना
- क्षेत्रक-विशिष्ट मुद्रा वित्तीय उत्पाद जैसेकि मुद्रा लेदर, मुद्रा टेक्सटाइल, आदि
- तेजी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 100 बैंक अनुमोदित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित परियोजनाओं को आदर्श बनाया गया है
- संपुष्ट in पोर्टल शुरू किया गया है, ताकि बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए प्रतिस्पर्धा आधार पर कार्य किया जाए।
- जीईएम (गवर्नमेंट इलेक्ट्रानिक बाजार) पोर्टल और ई-वाणिज्य प्लेटफॉर्म पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पंजीकृत करने के लिए अभियान चलाया जाए

- यह याद रखा जाए कि अतिरिक्त क्षमता से युक्त किंतु उपयुक्त परिश्रम को निम्न मात्रा में करने वाले सेक्टरों को बहुत अधिक ऋण देने के कारण दबाव में स्थित आस्तियां सृजित हुई हैं, जो मार्च 2014 तक बढ़कर 11.9 प्रतिशत हो गई है।

यूपीए सरकार के कुप्रबंधन के कारण फंसे ऋणों में भारी वृद्धि

पिछली यूपीए सरकार के कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार के कारण बैंकों के फंसे ऋणों में भारी वृद्धि हुई। इस हेतु स्पष्ट और पूर्णतः तैयार किए गए बैंक तुलन-पत्रों की जांच के लिए वर्ष 2015 की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से यह पता चला कि काफी अधिक मात्रा में अनर्जक आस्तियां सृजित हो गई हैं। दबाव में स्थित ऋण जिन्हें पूर्व में ऋण पुनर्गठन के लिए दी गई छूट के अंतर्गत चुकाया नहीं गया, के लिए हुई हानि के अंतर्गत स्थित ऋण का अनर्जक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया गया, जिसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अनर्जक आस्तियों की पहचान करके उन्हें निपटाने की प्रक्रिया आरंभ की तथा आपेक्षित हानि के लिए राशि उपलब्ध कराई।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सकल अनर्जक आस्ति 2015 के बाद से तेजी से बढ़ी और मार्च 2015 के 5.43 प्रतिशत (2,78,466 करोड़ रुपये) से बढ़कर जून 2017 में 13.69 प्रतिशत (7,33,137 करोड़ रुपये) हो गई। अनुमानित हानि के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि में पर्याप्त वृद्धि हुई। 2014-15 से 2017-18 की पहली तिमाही तक 3,79,080 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जबकि पूर्ववर्ती 10 वर्षों के दौरान केवल 1,96,937 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया था। यह दबाव में स्थित ऋण के कारण अनुमानित हानि से निपटने का सही उपाय था।

सरकार ने पीएसबी को पारदर्शी और अधिक दक्ष बनाने के लिए स्वच्छता अभियान के साथ अन्य सुधारों को पुनः पूंजीकृत किया है और उन्हें प्रारंभ किया है। इसके लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित किया गया था तथा पीएसबी में गैर-कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हेतु कदम उठाए गए थे।

पीएसबी के पुनःपूंजीकरण तथा आमूल-चूल परिवर्तन के लिए सरकार ने दिनांक 14-8-2015 को इंद्रधनुष योजना की घोषणा की। सरकार ने 2018-19 तक 1,80,000 करोड़ रु. की पूंजी की आवश्यकता की कल्पना की है। तदनुसार, सरकार ने 70,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया तथा बैंकों द्वारा 1,10,000 करोड़ रु. की पूंजी को बाजार से जुटाने का प्रस्ताव रखा। अभी तक सरकार ने पीएसबी में 51,858 करोड़ रु. की पूंजी लगायी है। एक्यूआर और एनपीए मान्यता के कराण दवाब के अंतर्गत पीएसबी अभी तक बाजार से 21,261 करोड़ रु. की पूंजी जुटा पाई है। दिसंम्बर, 2015 में पीएसबी के साथ आरबीआई द्वारा एक्यूआर निष्कर्षों को साझेदारी से पहले इंद्रधनुष के प्रारंभ ने पीएसबी को अन्य एनपीए तथा परिणामस्वरूप एक्यूआर के जरिए पता लगाई गई अनंतिम अपेक्षा के बावजूद सफलतापूर्वक बेसल III अनुपालनकर्ता बने रहने हेतु समर्थ बनाया है। वर्तमान निर्णय इंद्रधनुष योजना में ज्यादा सहायक होगा।

सरकार ने दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली एवं समाधान को आसान बनाने के लिए विभिन्न कानूनी बदलाव भी किए। दिवालियापन और शोधन अक्षमता संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए एक एकीकृत रूपरेखा के रूप में दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 अधिनियमित की गई। शीघ्र वसूली को आसान बनाने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हितों का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसएआरएफएईएसआई अधिनियम) और बैंकों को देय ऋण की वसूली एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 (जोकि ऋण वसूली प्राधिकरण को संचालित करता है), 2016 में संशोधित किए गये। इसके अतिरिक्त, सरकार को समर्थ बनाने के लिए इस वर्ष बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 को संशोधित किया गया, ताकि सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को यह प्राधिकृत करने के लिए समर्थ बनाया जा सके कि वह बैंको को दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे।

सरकार ने पीएसबी को पारदर्शी और अधिक दक्ष बनाने के लिए स्वच्छता अभियान के साथ अन्य सुधारों को पुनः पूंजीकृत किया है और उन्हें प्रारंभ किया है। इसके लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित किया गया था तथा पीएसबी में गैर-कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हेतु कदम उठाए गए थे।

पिछले तीन वर्षों में उठाये गये इन साहसी कदमों ने न सिर्फ परपरागत मुद्दों का समाधान किया है, बल्कि पीएसबी के पूंजीगत सामर्थ्य के पुनर्निर्माण के लिए सुधारों को और अधिक मजबूत बनाया गया है। मजबूत, बड़े बैंक बनाने की प्रक्रिया भारतीय स्टेट बैंक के एकीकरण से शुरू हो गई है एवं घोषित पुनःपूंजीकरण इसे और अधिक गति देगा। इसके लिए प्रत्येक पीएसबी की पूंजीगत सामर्थ्य पर आधारित विशिष्ट पहुंच अपनाई जाएगी।

दरअसल, इस अप्रत्याशित पुनः पूंजीकरण एवं पहलों से यह आशा की जाती है कि इससे निकट भविष्य में आर्थिक गतिविधियों को त्वरित करने में योगदान, रोजगार और अर्थव्यवस्था का विकास जैसे महत्वपूर्ण प्रभाव देखें जाएंगे। ■

मैं और हम

| दीनदयाल उपाध्याय |

प्रत्येक देशभक्त व्यक्ति की ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक ही है कि अपना देश वैभवशाली बने। राष्ट्र सुखी, संपन्न हो। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़े। बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशांति का अंत हो। न्याय सुलभ हो। आपसी झगड़े समाप्त हों। सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, भाषाई संकुचितताओं से ऊपर उठकर लोगों के सोचने, विचारने का तरीका हो। दलीय अभिनिवेशों से नेतागण मुक्त हों। भारत अपने राष्ट्रीय स्वरूप में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक सभी प्रकार के क्षेत्रों में लोक कल्याणकारी सिद्ध हो। जिसमें ऐसी इच्छा निर्माण नहीं होती हो, उसे भारतीय तो क्या मानव कहना भी कठिन है। स्व. मैथिलीशरणजी गुप्त के शब्दों में कहना हो तो ''जिसका न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है।' अपने देश को गौरवशाली देखने की इच्छा प्रत्येक जीवंत भारतीय के हृदय में उठना स्वाभाविक है।

अस्तु, राष्ट्र वैभव प्राप्त करने का अर्थ क्या है? कुछ लोग इस संदर्भ में अधूरे चिंतन की ओर बढ़ते हैं, जो राष्ट्रीय प्रगति को व्यक्तिगत लाभालाभ की दृष्टि से देखने वाले लोग हैं, उनके सोचने का दायरा केवल यहीं तक सीमित है कि राष्ट्र के वैभवशाली होने का अर्थ व्यक्ति का अपना जीवन सुखी संपन्न होना है। ऐसे लोग पढ़ाई–लिखाई, व्यापार, परिश्रम और रात–दिन की सारी दौड़–धूप इसी उद्देश्य से करते हैं कि 'मैं' व्यक्तिगत रीति से बड़ा–से–बड़ा हो जाऊं। उनकी महत्वाकांक्षाएं, बोलने में भले ही वे राष्ट्रीय दिखाई देती हों, किंतु वास्तविकता में वे व्यक्तिगत हैं। व्यक्तिगत आकांक्षा को लेकर किए गए कार्यों में भी कुछ–न–कुछ अध्यवसाय तो होता ही है, इसलिए कई बार ऐसा तर्क भी दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर प्रगति कर ले तो राष्ट्र की प्रगति हो जाएगी। किंतु वह तर्क महज एक धोखा है। राष्ट्र की सर्वतोमुखी प्रगति अकेले–अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकती। स्वयं व्यक्ति भी अपने आपमें कुछ नहीं कर सकता। यदि हम थोड़ी गहराई से विचार करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि 'मैं' का व्यावहारिक अर्थ है 'हम'।

मेरा नाम है दीनदयाल। इस नाम के साथ 'मैं' जुड़ा है। इसी से लोग मुझे पहचानते हैं। मेरा प्रत्येक कार्य इसी नाम से समझा जाता है। इसके साथ मेरा मोह होना स्वाभावकि है। यदि गहरी नींद में मुझे कोई इस नाम से पुकारता है तो मैं जाग उठता हूं। भारी भीड़ में हम जा रहे हों, बहुत कोलाहल हो, किंतु इसी समय इस कोलाहल को चीरकर कोई मेरा नाम लेकर बुलाए तो मैं सतर्क हो जाता हूं। उस कोलाहल और भीड़ में भी मेरा 'मैं' जाग्रत रहता है। इतना गहरा संबंध मुझसे मेरे इस नाम का है, किंतु यह नाम भी मुझे क्यों मिला? दीनदयाल के बदले मेरा नाम 'मि. जॉन' क्यों नहीं रखा गया? या विश्व में करोड़ों अन्य नाम हैं, फिर यही नाम क्यों रखा गया? कोई यह कह सकता है कि मां ने यह नाम रख दिया, किंतु मां ने यही नाम क्यों रखा? रूसी, चीनी, ईसाई, तुर्की, अरबी आदि नामों में कोई क्यों नहीं रखा? साफ है कि जिस समाज का मैं अंग हूं, उसके अनुरूप नामाभिधान हुआ।

अर्थ यह है कि जन्म के लिए मेरा संबंध पूज्य माता–पिता से है, किंतु जिस दिन मेरा नामकरण–संस्कार हुआ, मैं समाज का अंग बन गया। मेरी बोलने की शक्ति विकसित हुई तो भाषा भी मुझे समाज से मिली। मातृभाषा प्राप्त हुई। बड़े हुए तो सभ्य बने। इसका संबंध भी समाज से है। यानी समाज ने शिक्षा देकर बड़ा किया। जितने सुख–दुःख के अवसर आए, सबमें समाज उपस्थित हुआ। यहां तक कि सुख–दुःख की अनुभूतियां भी समाज ने दीं। घर मे कोई सुखदायी कार्य हो– विवाह, पुत्र जन्म या गृह निर्माण, तो इच्छा होती है कि चार लोग एकत्र हों। लोग न आएं तो बचत ही होगी, ऐसा सोचकर कोई संतोष नहीं कर लेता। बड़ी तीव्रता से चाहता है कि सब लोग सम्मिलित हों। समाज ने अच्छा कहा तो मन प्रसन्न होता है। बुरा कहा तो दुःखी। इस समाज के साथ इतना बड़ा संबंध स्थापित हो जाता है। यहां तक कि कोई समाज को बुरा कहे तो असहनीय हो जाता है। 'सबसे कठिन जाति अपमाना' वाली गोस्वामी तुलसीदासजी की उक्ति चरितार्थ हो जाती है। एक बार मैं रेलगाड़ी में प्रवास कर रहा था। सवारियों में आपसी तू–तू, मैं–मैं हो गई। बहस ने गाली–गलौज का रूप ले लिया, उनमें एक सज्जन पंजाबी थे। उन्हें संकेत कर सभी पंजाबियों पर एक व्यक्ति ने ताना कस दिया। बस फिर क्या था? वे बोले, ''देखो भाई, अब तक तुम मुझे ही उल्टा–सीधा कह रहे थे, किंतु अब तुमने सब पंजाबियों को बुरा बताया है। यह मुझे सहन नहीं हो सकता।'' इतना कहकर वे प्रतिकार करने की सिद्धता में लाल हो उठे। अब सोचना चाहिए कि सब पंजाबी लोग तो वहां उपस्थित थे नहीं, फिर भी इस व्यक्ति में ये जरूर थे।

इसी प्रकार कोई भगवान् रामचंद्र, कृष्ण, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, नानक, कबीर, रामदास, मीरा, तुलसी, गांधी पटेल आदि में से किसी को बुरा कहे तो हमारे अंदर बैठा यह 'मैं' जाग उठता है। तब केवल मेरे शरीर तक ही सीमित विचार नहीं होता। 'मैं' समाज बनकर उपस्थित होता है। 'मैं' का संबंध यदि शरीर तक ही होता तो कोई इन महापुरुषों को कितना ही कहता तो कुछ भी नहीं बिगड़ता किंतु इस 'मैं' में ये महापुरुष कहीं अवश्य विराजमान हैं। विदेशों में खेलों की प्रतियोगिताएं होती हैं। तब भारत की टीम विजयी होने पर हम प्रसन्नता से नाच उठते हैं, मिठाई बांटते हैं, आनंद होता है। भारतीय टीम हारने पर दुःख होता है, भारत की विजय पर 'मैं' प्रसन्न और हार में 'मैं' दुःखी होता हूं। इस 'मैं' में सारा देश भी आता है। इस प्रकार हम अनेक प्रसंगों पर यह पाते हैं कि 'मैं' वास्तव में 'हम' ही है।

राष्ट्र के वैभव से ही व्यक्ति का महत्त्व

'हम' ही महत्वपूर्ण हैं। सब कुछ जीवन पर ही निर्भर है। वैभव भी सामूहिक जीवन की एक विशेष स्थिति का नाम है। एक सज्जन विदेशों की यात्रा कर लौटे हैं। उन्होंने लेख लिखकर बहुत दुःख प्रकट किया। मैंने पूछा, इतने दुःखी क्यों हैं? तो बोले, ''क्या बताऊं, विश्व के सभी देशों में हिंदुस्तान के संबंध में एक ही धारणा है कि यह भिखारियों का देश है।'' मैंने उनसे पूछा, ''तुमने तो भीख नहीं मांगी?'' वे बोले, ''नहीं, किंतु यह कैसे कहा जा सकता है कि भारत भीख मांग रहा है?'' यानी राष्ट्रीय अपमान में हम सबका अपमान है। उसी प्रकार जब भारत–पाक युद्ध के समय भारतीय सैनिक शत्रु को पराजित कर मोर्चे पर आगे बढ़ने लगे तो जीत की खुशी में नारे लगाए गए। राष्ट्रीय सफलता पर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करने लगें। यानी राष्ट्र के वैभव में हमारा वैभव निहित है।

वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन नाशवान है, फिर भी भगतसिंह को सब याद करते हैं। हकीकत राय, गुरु तेग बहादुर को याद करते हैं। एक लंबी परंपरा है, जिनका स्मरण होता है। इन सब बलिदानी महापुरुषों ने अपने शरीर की परवाह नहीं की। यह 'हम' ही था, जिसने 'मैं' को इतना ऊंचा उठने की प्रेरणा दी। हंसते–हंसते बलिदान हो गए। कहा कि शरीर नश्वर है। समाज अमर है। समाज को जीवित रखने के लिए व्यक्ति ने बलिदान दिए। समाज ने उन्हें अपनी स्मृतियों में संजोकर अमर बना दिया। दोनों अमर हुए। इन बलिदानों को क्या आत्महत्या कहा जाएगा? नहीं। बलिदान और आत्महत्या में अंतर है। आत्महत्या 'मैं' तक सीमित भावना है, इसलिए गलत है किंतु सही कार्य 'हम' के लिए होता है तो बलिदान कहा जाता है। शरीर जब देश के लिए, समाज के लिए अर्पित हो तो गौरव की बात है। उसमें चिंता किस प्रकार की? यह वरेण्य है। इससे समाज को शक्ति मिलती है। बलिदान से श्रेष्ठ कार्य के पौधे सींचे जाते हैं। 'मैं' का वास्तविक अर्थ 'हम' गुंजित होता है। जहां 'हम' यानी सामूहिक उत्तरदायित्व उभरा कि शक्ति का प्रस्फुटन होता है। इसलिए बलिदान राष्ट्र को नवचैतन्य प्रदान करने वाले सिद्ध होते हैं।

मोक्ष भी समष्टिगत है

'हम' ही वह मूलभूत तथ्य है, जो 'मैं' को सार्थक बनाता है। आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास इसी तथ्य में निहित हैं। कोई व्यक्ति यदि हिमालय की किसी कंदरा में जाकर योग–ध्यान करें और 'मैं' से चलकर 'हम' तक पहुंचे, केवल व्यक्तिगत मोक्ष की आकांक्षा से ही सब कुछ करे, योगाभ्यास करे, तो भी उसे मुक्ति नहीं मिल नहीं सकती। मुक्ति इतनी छोटी चीज नहीं है जो समाज को छोड़कर किसी एक को एकांत में मिल जाए। किसी प्रकार की सिद्धि भले ही प्राप्त हो जाए तथापि वह सिद्धि तब तक बेकार ही है, जब तक वह अपने चारों ओर फैले समाज बंधुओं को उन्नत करने में समायोजित न हो। कुछ लोगों की ऐसी गलत धारणा है कि समाज अधःपतित रहते हुए भी केवल वही अकेले मुक्ति भी समष्टिगत है। जब समाज मुक्त होगा, तो ऊंचा उठेगा। उन्नत होगा, तभी व्यक्ति को शांति मिल सकती है। इसलिए संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाले भी लोक संग्रह का दायित्व ग्रहण करते हैं। लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य में वर्णित कर्मयोग का भी यही निष्कर्ष है। शास्त्रों में वर्णित एक श्लोक उद्धृत कर उन्होंने कहा कि अपना धर्म–कर्म छोड़कर जो कृष्ण–कृष्ण चिल्लाते हैं, वे पापी हैं। कृष्ण स्वयं धर्म की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहे। 'धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे–युगे' की घोषणा हुई। भगवान् इसी के लिए अवतरित होते हैं। ऐसा वर्णन हमें सुनने को नहीं मिलता कि भगवान् का अवतार हुआ तो ये कहीं किसी गुफा में बैठकर एकांत मुक्ति की साधना में लग गए। भगवान् राम का चरित्र हमारे सामने है। उखड़ी हुई मर्यादाओं और च्युत लक्ष्यों को पुनः स्थापित कर धर्म की विजय उनके आश्रय से प्राप्त हुई। इसलिए समाज को उन्नत बनाने का काम भगवान् का काम है। अपने हित के लिए किया गया काम शैतान का काम है। राष्ट्रभक्ति, समाजभक्ति ही भगवान् भक्ति है। ■

वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन नाशवान है, फिर भी भगतसिंह को सब याद करते हैं। हकीकत राय, गुरु तेग बहादुर को याद करते हैं। एक लंबी परंपरा है, जिनका स्मरण होता है। इन सब बलिदानी महापुरुषों ने अपने शरीर की परवाह नहीं की। यह 'हम' ही था, जिसने 'मैं' को इतना ऊंचा उठने की प्रेरणा दी। हंसते–हंसते बलिदान हो गए।

(-राष्ट्रधर्म, सितंबर 5, 1956) क्रमशः...

राष्ट्रवादी चिंतक के. आर. मलकानी

(19 नवम्बर 1921-27 अक्टूबर 2003)

केवलराम रतनमल मलकानी (के. आर. मलकानी) एक प्रखर चिंतक, राजनेता, आदर्शवादी, सैद्धांतिक पत्रकार व कर्मयोगी थे। वे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं पांडिचेरी के राज्यपाल रहे। वह एक समर्थ विचारक एवं लेखक भी थे। मलकानी जी का जन्म 19 नवंबर, 1921 को हैदराबाद (सिन्ध) में हुआ था। युवाकाल में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए और 1941 से 2003 तक वे आजीवन संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक रहे। मलकानी जी भारतीय जनसंघ के जन्मकाल से ही उसके सिद्धान्तकार बन गए। उनके ही आग्रह पर पं. दीनदयाल उपाध्याय ने आर्गेनाइजर में साप्ताहिक 'पॉलिटिकल डायरी' लिखना प्रारंभ किया।

मलकानी जी अन्तर्मुखी प्रवृत्ति के थे। अनावश्यक प्रदर्शन और मिलना-जुलना उनके स्वभाव में नहीं था, किन्तु उनका अन्तःकरण निर्मल और स्वभाव बहुत पारदर्शी था। लाग-लपेट की उन्हें आदत नहीं थी। जब भी वे बात करते खुलकर बात करते थे। वे निर्भीक थे, निःस्वार्थी थे। उनका जीवन बहुत सादा और कठिन था। 1971 में 'मदरलैंड' नामक दैनिक पत्र प्रारंभ हुआ। मदरलैंड के संपादन का जिम्मा व प्रबंधन मलकानी जी पर था। हालांकि प्रारम्भ में डी. आर. मनकेकर इसके संपादक थे, लेकिन वास्तविक संपादन का कार्य मलकानी जी ही देखते थे। आपातकाल की घोषणा के बाद मलकानी जी सबसे पहले पकड़े गए और पूरे उन्नीस महीने जेल काटकर आपातकाल समाप्त होने पर छोड़े गए। उनके जेल जीवन की कहानी उनकी कलम से 'मिडनाईट नॉक' नामक पुस्तक के रूप में सामने आयी। 'मदरलैंड' बंद होने के बाद मलकानी जी पुनः आर्गेनाइजर के संपादक पद पर वापस आये और 1982 में 62 वर्ष की आयु में आर्गेनाइजर के संपादक दायित्व से निवृत्त हुए। मलकानी जी ने भाजपा के मुखपत्र 'बीजेपी टुडे' का भी संपादन किया।

विभाजन की वेदना उनके मन में गहरी थी, अखण्ड भारत का सपना उनकी आंखों में था। इसके लिए वे सदैव संघर्ष करते रहे। साथ ही मलकानी जी ने दिल्ली में सिंधी समाज को संगठित करने के लिए मंच की स्थापना की और वे उसके पहले अध्यक्ष बने। मलकानी जी भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय कार्यसमिति में आमंत्रित रहते थे। जब उन्हें उपाध्यक्ष पद सौंपा गया तब उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान के गैर राजनीतिक चरित्र का आदर करते हुए उसके दायित्वों से मुक्ति ले ली और वे उपाध्यक्ष के नाते भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय में पूरे समय बैठने लगे। 1994 से 2000 तक वे राज्य सभा के सदस्य रहे, पर उनकी कलम कभी रुकी नहीं।

मलकानी जी आजन्म योद्धा रहे। संपादक के पत्र स्तंभ हो, या टेलीविजन पर बहस, हर जगह मलकानी जी का राष्ट्रवादी स्वर गूंजता रहा। वे राष्ट्रवाद के विरोधियों से लोहा लेते रहे। वे जुलाई 2002 में पांडिचेरी के उपराज्यपाल पद पर नियुक्त हुए। राजभवन में भी वे सबको स्मरण करते रहे और लेखन में जुटे रहे। 27 अक्टूबर 2003 को उन्होंने अंतिम सांस ली। मलकानी जी का जीवन आदर्शवादी, सिद्धान्तनिष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रकाशस्तंभ है, प्रेरणास्रोत है। ■

जम्मू-कश्मीर में भाजपा युवा नेता गौहर अहमद भट की नृशंस हत्या

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों ने 2 नवंबर को 30 वर्षीय भाजपा युवा नेता श्री गौहर अहमद भट की नृशंस हत्या कर दी। दरअसल, दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों ने पहले भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री गौहर अहमद भट को अगवा किया और बाद में उनकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। उसके शरीर पर टार्चर के निशान थे।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पार्टी की युवा शाखा के नेता श्री गौहर हुसैन भट की मौत पर शोक प्रकट किया। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, 'जम्मू कश्मीर में शोपियां के हमारे भाजयुमो जिला प्रमुख गौहर अहमद की नृशंस हत्या के बारे में जानकर दुःख हुआ।' श्री शाह ने कहा कि आतंकवादी युवाओं को एक बेहतर भविष्य चुनने से नहीं रोक सकते। इसके आगे उन्होंने लिखा, 'भाजपा गौहर अहमद के परिवार के साथ खड़ा है।' ■

कांग्रेस ने मैदान छोड़कर अपनी हार स्वीकार कर ली है : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के ऊना, कुल्लू और पालमपुर में आयोजित विशाल रैलियों को संबोधित किया और राज्य की जनता से प्रदेश के विकास के लिए श्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा की तीन-चौथाई बहुमत से सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में चारों ओर, हर तरफ कमल ही कमल खिला नजर आ रहा है और चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने मैदान छोड़कर हिमाचल में अपनी हार स्वीकार कर ली है।

श्री मोदी ने कहा कि इस बार हिमाचल की जनता के पास इतिहास रचने का अवसर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हवा का रुख जानने पहचानने की जरूरत नहीं, यहां तो आंधी चल रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हिमाचल की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का चुनाव न तो भाजपा के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और न ही भाजपा के नेता, बल्कि यहां का चुनाव यहां की जनता लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश के चुनाव की कोई चिंता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता के साथ-साथ कांग्रेस को भी यह मालूम है कि हिमाचल में कांग्रेस की नैया डूबने वाली है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार अलग हो ही नहीं सकते। ये दोनों एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी जमानती पार्टी है, जब इसके नेता ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं तो वे भ्रष्टाचार दूर करने की बात कैसे कर पायेंगे। उन्होंने कहा कि यदि हमें भविष्य बचाना है तो देश को भ्रष्टाचार रूपी बुराई से बाहर निकालना पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि देवभूमि में दानव वृत्ति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खनन माफिया, वन माफिया, ट्रांसफर माफिया, टेंडर माफिया और ड्रग माफिया - इस पांच प्रकार की कांग्रेस की दानव वृत्ति से हमें हिमाचल प्रदेश को बचाना है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से एक रुपया चलता है, लेकिन जनता के पास केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं, देश जानना चाहता है कि आखिर वह कौन सा पंजा था जो ऐसा करता था। उन्होंने कहा कि हमने आधार के साथ सिलिंडर को जोड़ा, जिससे लगभग 57000 करोड़ रुपये की बचत हुई और अब ये रुपये गरीब जनता की भलाई के काम आ रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि हमें विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो चुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ 8 नवंबर को कांग्रेस मोदी का पुतला जलाने वाली है, क्योंकि यह वही 8 नवंबर है जब उनकी काली कमाई के 500 और 1000 के पुराने नोट कूड़े के ढेर बन गए। उन्होंने कहा कि आम जनता को इससे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने देश हित में इसे दिल से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता नोटबंदी से नाराज नहीं है, लेकिन कुछ लोग एक साल बाद भी रो रहे हैं क्योंकि उनका काला धन जो बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जनता के आशीर्वाद की ताकत के कारण कठोर फैसले ले रहा हूं और देश को लूटने वालों को उनकी जगह दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के समय ही तब के वित्त मंत्री श्री यशवंत राव चह्वाण ने बड़े नोट बंद करने की वकालत की थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने सत्ता बचाए रखने के लिए इस पर अमल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि तब इंदिरा जी ने कांग्रेस से ज्यादा हिन्दुस्तान की चिंता की होती तो हमें इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ता। कांग्रेस ने नहीं किया इसलिए मुझे करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि नोटबंदी का निर्णय नहीं लिया जाता तो शायद कभी पता भी नहीं चल पाता कि कश्मीर के आतंकवादियों को पैसा कहां से आता है और उन पर शिकंजा भी नहीं कस पाता। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जनता हमारे साथ हो गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि पैसा तो पाकिस्तान से आता है और ये हमें गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आये दिन कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, अब ऐसी घटनाएं नहीं के बराबर हो

रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस 8 नवंबर को ब्लैक डे मनायेगी तो यह देश एंटी ब्लैकमनी डे मनाकर रहेगा। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को ब्लैक डे मना कर कांग्रेस यह दवाब बनाना चाहती है कि मोदी और आगे कुछ न करे, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। जिन्होंने देश को लूटा है, उन्हें देश को लौटाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण तीन लाख कंपनियों के काले कारोबार का पता चला, केवल 5000 कंपनियों के सैम्पल टेस्ट में ही लगभग 4000 करोड़ रुपये के काले धन का पता चला है। पूरे तीन लाख कंपनियों की जांच होगी तो पता नहीं, कितने के काला-धन का पता चलेगा।

श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ हमें देश को बुराइयों से बचाना है तो दूसरी तरफ देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि विकास को पहले अटकाना, फिर लटकाना और बाद में भटकाना, यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। उन्होंने कहा कि शिमला के पास एक टनल का शिलान्यास श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, लेकिन कांग्रेस की यूपीए सरकार ने उस योजना को लटका कर रखा लेकिन हमने तीन ही साल में इसे लगभग पूरा कर दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि हमने एक राष्ट्र, एक कर के स्वप्न को साकार

करते हुए जीएसटी लागू किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी से कारोबार और आसान होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापारी अथवा व्यापारी संगठन ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया है, लेकिन किसी भी बड़े परिवर्तन में थोड़ी-बहुत समस्याएं होती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तीन महीनों में देखेंगे कि कहां -कहां कठिनाइयां आ रही हैं और जहां-जहां दिक्कतें आयेंगी, उसे दूर करने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापार जगत की जो समस्याएं आईं, उसका हमने समाधान किया। कुछ और सुधार बाकी है जो राज्यों के विरोध के कारण अटक गए थे। उन्होंने कहा कि हमने इन समस्याओं को दूर करने के लिए कमिटियां बनाई और आगामी 9-10 नवंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक उन समस्याओं को भी दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार सबसे चर्चा करके देश की भलाई के लिए उत्तम से उत्तम निर्णय लेती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बेनामी संपत्ति की बीमारी ऐसी फैल गई थी कि मध्यम वर्ग का जीना मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने क़ानून तो बनाया, लेकिन 20 साल तक इस ठंडे बस्ते में दाल दिया, क्योंकि उनको खुद अपने फंसने का डर था। उन्होंने कहा कि हमने इसे लागू किया, जिन्होंने देश की गरीब जनता का हक़ छीन कर पैसा इकट्ठा किया है, उन्हें देश की जनता को लौटाना ही पड़ेगा।

श्री मोदी ने कहा कि टूरिज्म के क्षेत्र में हिमाचल में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि टूरिज्म बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, गरीब की कमाई होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर हमें टूरिज्म को बनाना है तो हिमाचल को रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना होगा। उन्होंने हिमाचल की जनता को याद दिलाते हुए कहा कि दशकों से ऊना-हमीरपुर रेल लाइन का काम अटका पड़ा था। कांग्रेस की सरकार ने घोषणा तो की लेकिन कोई काम नहीं हुआ, इस काम की शुरुआत हमने की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जब धूमल जी की सरकार थी और दिल्ली में अटल जी की सरकार थी, तब टूरिज्म को इतना बढ़ावा दिया कि हिमाचल टूरिज्म डेस्टिनेशन में टॉप पर आ गया था। उन्होंने कहा कि एक बार फिर ऐसा मौका आया है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिमाचल में भी बनने वाली भाजपा सरकार हिमाचल को विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जाने का तैयार है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 70 साल हो गए, सवा सौ करोड़ देशवासी कब तक इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने पीने का पानी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, युवाओं की कमाई और बुजुर्गों की दवाई की व्यवस्था शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सरकारें पहले भी थीं, अधिकारी पहले भी थे लेकिन आज ग्राम सड़क योजना के तहत ज्यादा सड़कों का निर्माण क्यों हो रहा है। पहले एक दिन में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग बनते थे, आज उससे लगभग दुगुना बन रहा है, जितनी रेल लाइनें पहले बनती थी आज उसका दुगुना निर्माण हो रहा है, आखिर यह संभव कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार का एकमात्र उद्देश्य देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का भविष्य एक ही बात पर निर्भर करता है कि हम विकास को प्राथमिकता कैसे दें, हर दिशा में विकास कैसे करें, गरीब से गरीब तक विकास कैसे पहुंचाएं और युवा पीढ़ी की तरक्की के लिए काम कैसे करें इसलिए हमारी कोशिश यह है कि देश में विकास पर ही चर्चा होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश के विकास से महरूम रखने के लिए सजा देने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तरक्की में यदि विकास का डबल इंजन लग जाय तो देवभूमि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सकता है। उन्होंने हिमाचल की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि हिमाचल की जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी मजबूती के साथ सजा दे, ताकि पूरे देश में यह संदेश जाय कि हिमाचल प्रदेश अब भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकता। ■

'कांग्रेस आत्मचिंतन करे कि देशभर में जनता उन्हें सजा क्यों दे रही है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के रैहन (कांगड़ा) और नाहन में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से प्रदेश को विकास से महरूम रखनेवाली कांग्रेस की भ्रष्टाचारी वीरभद्र सरकार को उखाड़-फेंक कर भारतीय जनता पार्टी की लोक-कल्याणकारी सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब तक हिमाचल में किसी को भी जितनी सीटें नहीं मिली थी, जितने वोट नहीं मिले थे, उससे भी अधिक वोट और विकास के संकल्प के साथ इस बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को लूटा है, उनकी विदाई का वक्त आ गया है। उन्होंने हिमाचल की जनता से अपील करते हुए कहा कि आप आगामी 9 नवंबर को जब बटन दबाने जाएं तो वजीर राम सिंह पठानिया के बलिदान को याद रखें, तभी सही सरकार बनेगी और हिमाचल का भाग्य बदलेगा। उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का राज्य में कमल खिलाने के संकल्प को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि अब देश कांग्रेस पार्टी से कोई आशा नहीं रख सकती, यह एक नॉन-सीरियस जमावड़ा बन चुका है, कांग्रेस अब लाफिंग क्लब बन कर रह गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जमानत पर हैं और अपने घोषणापत्र में वे कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, यह मजाक नहीं तो और क्या है? उन्होंने कहा कि सेना के जवानों की शहादत के बावजूद वीरभद्र सिंह जी यह कहें कि कश्मीर की आजादी की मांग सही है, तो यह हमारे वीर शहीदों का अपमान है, हिमाचल इसे सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, अब जबकि उनके पास कुछ नहीं बचा है, लोग कांग्रेस का स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तब भी कांग्रेस हिमाचल में जीत का दिवास्वप्न देख रही है।

श्री मोदी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में यदि काम गलत इरादे से किया जाए, तो जनता और देश कभी माफ नहीं करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आत्मचिंतन करे कि देशभर के कोने-कोने में जनता उन्हें सजा क्यों दे रही है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही, यह जातिवाद फैलाने वाली और सड़ी हुई सोच का नमूना बन चुकी है, जिससे हम देश को मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उस समय जनसंघ का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू कहा करते थे कि हम जनसंघ को जड़-मूल से उखाड़कर फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि हम दिये की रोशनी में जले थे और कीचड़ में कमल भी खिला दिए। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की सड़ी हुई सोच के नमूने को मिटाने के लिए जन-जागरण अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देश को कांग्रेस की सड़ी हुई सोच से मुक्ति दिलाने के लिए है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वीरभद्र सरकार ने पांच प्रकार के दानवों को पैदा किया और इन पांच

प्रकार के दानवों खनन माफिया, वन माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसफर माफिया और टेंडर माफियाओं ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है, अब इन्हें राज्य से समूल नष्ट करने का समय आ गया है।

श्री मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में श्री शांता कुमार की भाजपा सरकार को राज्य के लोग पानी पहुंचाने के लिए किये गए अद्भुत प्रयास को लेकर याद करते हैं, जबकि श्री प्रेम कुमार धूमल सरकार को पहले पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि तब मीडिया सर्वे में भी हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान दिया जाता था। उन्होंने हिमाचल की जनता से पूछते हुए कहा कि अब आप ये बताएं कि कांग्रेस की वर्तमान वीरभद्र सरकार की पहचान क्या है, तो इसका एक ही जवाब है - भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से एक ऐसी सरकार देंगे जो हिमाचल के खजाने पर किसी का भी पंजा नहीं पड़ने देगी। कोई पंजा राज्य के खजाने पर डाका नहीं डाल सकेगा। उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल से भ्रष्टाचार रूपी दीमक को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, हम जनता के साथ मिलकर एक 'भव्य एवं दिव्य हिमाचल' का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान विकास में ही निहित है और भाजपा हिमाचल को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को पता ही नहीं है कि वे क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और किसलिए बोलते हैं। उन्होंने कहा क्या कोई देश की सेना के पराक्रम पर कोई प्रश्न कर सकता है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी सेना के जवानों की वीरता पर ही सवाल खड़े करती है। ऐसी पार्टी को सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि वन रैंक, वन पेंशन के नाम पर कांग्रेस ने जवानों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा करने का काम किया था, ओआरओपी का काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन की तीन किस्तें दी जा चुकी है, चौथी किस्त भी जल्द जारी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को भी पता है चुनाव में उसका सूपड़ा साफ होगा और 18 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो प्रदेश में धूमल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देवभूमि हिमाचल के विकास के लिए कटिबद्ध है, राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई और बुजुर्गों की दवाई के लिए काम किया जाएगा। ■

कांग्रेस सरकार ने राज्य में विकास की सभी संभावनाओं को ख़त्म कर दिया है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 30 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में बनीखेत (डलहौजी) और चल्वारा (जवाली) में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और हिमाचल के विकास के लिए कांग्रेस की भ्रष्टाचारी वीरभद्र सरकार को उखाड़ कर दो-तिहाई की बहुमत से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने हिमाचल की मौजूदा कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए राज्य के विकास के प्रति उसकी उदासीनता व अकर्मण्यता को लेकर वीरभद्र सरकार पर करारा प्रहार किया।

श्री शाह ने कहा कि पांच साल से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की वीरभद्र सरकार चल रही है। उसने पूरे देश में देवभूमि के नाम को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि वह देवभूमि जो कुदरती सौंदर्य और पर्यटन के लिए जानी जाती थी, शूरवीरों की भूमि के रूप में जिसकी सराहना कश्मीर से कन्याकुमारी तक होती थी, आज उस हिमाचल प्रदेश को यहां के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने माफिया की भूमि बनाकर रख दी है। उन्होंने कहा कि जब भी, जहां भी और जैसे भी भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, वीरभद्र सिंह जी का नाम सुर्ख़ियों में हमेशा के लिए आ जाता है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके परिवार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप न हो, पूरा का पूरा परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता के लिए निर्णय लेने का वक्त आ गया है कि उन्हें राज्य में माफिया राज लाने वाली सरकार चाहिए। भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली सरकार चाहिए या हिमाचल को मॉडल स्टेट बनाने वाली सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विकास की काफी सारी संभावनाएं हैं, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने राज्य में विकास की सभी संभावनाओं को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे पांच साल वीरभद्र सिंह जी केवल घोषणा और भूमिपूजन ही करते रहे, उद्घाटन का एक भी दिन नहीं आया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के इतिहास में भूमिपूजन करने वाले मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध होने वाले हैं।

श्री शाह ने कहा कि अपराध की बात करें, चाहे वह महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अपराध की बात हो या फिर अन्य, लगभग हर श्रेणी के अपराध में हिमाचल प्रदेश में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य को भ्रष्टाचार में नंबर एक बना कर रख दिया है, यही वीरभद्र सिंह जी की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया बेरोकटोक अवैध खनन कर रहे हैं, वन माफिया पेड़ों को काट रहे हैं, ड्रग माफिया आने वाली नई नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, ट्रांसफर माफिया ट्रांसफर व पोस्टिंग में पैसे लूट रहे हैं, राज्य में हर तरफ अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास

के प्रश्न जस के तस हैं, लेकिन वीरभद्र सरकार ने माफियाओं की सारी मुश्किलें जरूर हल कर दी है। उन्होंने कहा कि एक ओर हिमाचल प्रदेश में माफियाओं की और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त एवं निर्णायक सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हिमाचल प्रदेश के साथ दिल का रिश्ता है, उन्होंने यहां पर संगठन की मजबूती के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने भी अपना पूरा आशीर्वाद देकर लोक सभा चुनाव में सभी की सभी सीटें भाजपा की झोली में डाल दी।

श्री शाह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीरों की भूमि है। उन्होंने कहा कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से देश के जवान 'वन रैंक, वन पेंशन' की मांग करते आ रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी-मनमोहन सिंह की सरकार तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक साल में ही 'वन रैंक, वन पेंशन' का प्रश्न समाप्त करके देश के भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हमने तो हिमाचल की जनता को तीन साल का हिसाब दे दिया, अब वीरभद्र सिंह को हिमाचल की जनता को जवाब देना चाहिए कि यह 71,000 करोड़ रुपये कहां गए, वे पैसे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र की सहायता से आईआईएम की आधारशिला रखी गई है, ईएमएस की आधारशिला रखी गई है, तीन नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में बनाया जा रहा है, लगभग 76 हजार एलईडी बल्ब वितरित किये गए हैं, 16 हजार गरीब महिलाओं को एलपीजी के कनेक्शन

उपलब्ध कराये गए हैं और बहुत सारे युवाओं को मुद्रा बैंक के माध्यम से ऋण देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, हमने तो हिसाब दे दिया है, अब जब आप हिमाचल में आइएगा तब हिमाचल की सरकार ने पांच साल में राज्य के विकास के लिए क्या किया है, इसका हिसाब जरूर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि आप पांच सालों में हिमाचल के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, 70 मार्गों को हमने नेशनल हाइवे में तब्दील किया, लेकिन आप के मुख्यमंत्री उसका डीपीआर भी नहीं बना सके।

श्री शाह ने कहा कि यदि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो राज्य से माफियाओं को ख़त्म करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू की जायेगी। साथ ही, खनन, वन एवं पुलिस - इन तीनों को मिलाकर एक जॉइंट टास्क फ़ोर्स बनाया जाएगा जो खनन माफियाओं को जेल भेजने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने पर ई-टेंडर के जरिये सारे टेंडर निकाले जायेंगे, ताकि भ्रष्टाचार न हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने लोकायुक्त के मामले में विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया, लेकिन मैं हिमाचल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल की भाजपा सरकार लोकायुक्त विपक्ष को भरोसे में लेकर नियुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि शिमला और धर्मशाला में युवाओं के लिए युवा हॉस्टल बनाए जायेंगे, हर जिले में मिनी स्टेडियम और खेल एकेडमी बनाई जायेगी, किसानों के लिए सेब, आम और संतरे का समर्थन मूल्य बढ़ाने का भी उल्लेख हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में किया है। उन्होंने कहा कि पालमपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, युवाओं का पहाड़ से पलायन हो रहा है, इसे रोकने के लिए पूरे हिमाचल में हम जैविक खेती को बढ़ावा देकर कृषि को और मुनाफे वाली बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि IT कनेक्टिविटी बढ़ाकर हिमाचल को हम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हब बनायेंगे, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने पर वर्ग तीन और चार से इंटरव्यू को ख़त्म करेगी। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि ट्रांसफर इंडस्ट्री भाजपा सरकार में नहीं चलेगी, ट्रांसफर के लिए एक पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वीर शहीदों के लिए हर जिले में शहीद स्मारक और पार्क बनाए जायेंगे। ■

'भाजपा हिमाचल को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाती है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 1 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के सिराज (मंडी) और हमीरपुर में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि भाजपा को हिमाचल प्रदेश की जनता से मिल रहे अपार प्यार और समर्थन से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में तीन-चौथाई की बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को स्वप्न आता है कि हिमाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस को यह याद होना चाहिए कि 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश में हुए हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी पराजय हुई है और भाजपा की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की पराजय निश्चित है। उन्होंने कहा कि पहले अच्छी विजय का मानक दो-तिहाई बहुमत माना जाता था, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विजय का मानक तीन-चौथाई बहुमत को माना जाता है।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने तीन साल में क्या-क्या किया है, इसका जवाब देने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूं। हमारी तो परंपरा जनता को पाई-पाई का हिसाब देने की रही है, लेकिन हिसाब तो हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस से मासूम गुड़िया के कातिलों, होशियार सिंह के हत्यारों और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के भ्रष्टाचार पर मांग रही है। उन्होंने कहा कि 14 साल की मासूम गुड़िया के साथ दरिंदगी होती है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन वीरभद्र सिंह के माथे पर जूं तक नहीं रेंगती। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी और राज्य की जनता के दवाब में सीबीआई जांच होती है तो रक्षक ही भक्षक निकलते हैं। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी और हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जहां देवभूमि की माताओं-बहनों को इंसाफ के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी ने देवभूमि हिमाचल को माफियाओं की भूमि बना कर रख दिया है, राज्य में हर तरफ भू-माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, ट्रांसफर माफिया आदि माफियाओं का बोलबाला है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हिमाचल में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से आगे बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से कि आखिर वे किस तरह के हिमाचल प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि पांच साल से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की वीरभद्र सरकार चल रही है, उसने राज्य के विकास को अवरुद्ध करके रख दिया है।` ■

डिमोनेटाईजेशन के एक वर्ष

मई 2014 में जिम्मेदारी ग्रहण करने के तुरंत बाद, केन्द्र की भाजपानीत राजग सरकार ने काले धन पर एसआईटी का गठन करके काले धन के खतरे से निपटने की लोगों की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। हमारा देश इस बात से भलीभांति अवगत है कि किस तरह इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का तब की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने कई वर्षों तक अवहेलना की थी।

अरुण जेटली

नवंबर 8, 2016 भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद किया जाएगा। यह दिन देश को "काले धन की खतरनाक बीमारी" से दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के संकल्प को दर्शाता है। हम भारतीयों को, भ्रष्टाचार और काले धन के संबंध में "चलता है" के रवैये के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था और इसका सबसे बड़ा कुप्रभाव विशेष रूप से मध्यम वर्ग और समाज के निचले तबकों को भुगतना पड़ा था। भ्रष्टाचार और काले धन के अभिशाप को जड़ से उखाड़ फेंकने का लंबे समय से हमारे समाज के बड़े हिस्से की यह एक हार्दिक इच्छा थी, जो मई 2014 में संपन्न हुए आम चुनाव में लोगों के फैसले में प्रकट हुई थी।

मई 2014 में जिम्मेदारी ग्रहण करने के तुरंत बाद, इस सरकार ने काले धन पर एसआईटी का गठन करके काले धन के खतरे से निपटने की लोगों की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। हमारा देश इस बात से भलीभांति अवगत है कि किस तरह इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का तब की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने कई वर्षों तक अवहेलना की थी। बेनामी संपत्ति कानून के क्रियान्वयन में 28 साल की देरी कांग्रेस सरकार द्वारा काले धन से लड़ने के प्रति इच्छाशक्ति की कमी का एक और उदाहरण था।

इस सरकार ने काले धन के खिलाफ लड़ाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विगत तीन वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और क़ानून के पूर्व प्रावधानों को अच्छी तरह से समझते हुए इसे नियोजित तरीके से लागू किया। SIT के गठन से इन फैसलों की शुरुआत हुई और फिर विदेशी संपत्ति के संदर्भ में आवश्यक क़ानून बनाने के साथ-साथ डिमोनेटाईजेशन और जीएसटी को क्रियान्वित कर काले धन के खिलाफ लड़ाई की निर्णायक पहल की गई।

जब देश "एंटी-ब्लैक मनी डे" में भाग ले रहा है, तब एक बहस शुरू हुई है कि क्या विमुद्रीकरण ने किसी निर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति की है। यह नोट उक्त उद्देश्यों के संबंध में लघु एवं दीर्घ काल के लिए डिमोनेटाईजेशन के सकारात्मक परिणाम को उल्लेखित करने का प्रयास है।

आरबीआई ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया है कि 30.6.2017 तक 15.28 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य के निर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) वापस जमा किए गए हैं। 8 नवंबर,

2016 को बकाया एसबीएन 15.44 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के थे। 8 नवंबर, 2016 को डिमोनेटाईजेशन के वक्त कुल 17.77 लाख करोड़ रुपये की मुद्रा चलन में थी।

डिमोनेटाईजेशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को एक कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था में तब्दील करना था और इस तरह से व्यवस्था में से काले धन के प्रवाह को भी कम करना था। आधार स्थितियों से परिसंचरण में मुद्रा में कमी दर्शाती है कि इस निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त हुई है। सितंबर, 2017 को समाप्त हुए आधे साल के लिए "प्रचलन में मुद्रा" का प्रकाशित आंकड़ा 5.89 लाख करोड़ रुपये है। यह (-) 1.39 लाख करोड़ रुपए के सालाना वेरिएशन को रेखांकित करता है, जबकि इसी अवधि के लिए पिछले वर्ष के दौरान सालाना वेरिएशन (+) 2.50 लाख करोड़ रुपये था। इसका मतलब यह है कि मुद्रा संचरण में पिछले साल की तुलना में 3.89 लाख करोड़ रुपये की कमी हुई है।

हमें व्यवस्था में से अतिरिक्त मुद्रा क्यों हटानी चाहिए? हमें नकद लेन-देन में कटौती क्यों करनी चाहिए? यह सामान्य ज्ञान है कि नकदी गुमनाम होती है। जब विमुद्रीकरण लागू किया गया था, तो इसका एक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में नकदी जमा रखने वालों की पहचान भी करना था। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में 15.28 लाख करोड़ रुपये की वापसी के बाद अब अर्थव्यवस्था में नकदी रखने वाले लगभग सभी धारकों की पहचान हो गई है। अब कोई गुमनाम नहीं है। इस इनफ्लो से, विभिन्न अनुमानों के आधार पर संदिग्ध लेन-देन में शामिल होने वाली राशि 1.6 लाख करोड़ रुपये से लेकर 1.7 लाख करोड़ रुपये तक की है। अब यह कर प्रशासन और अन्य

प्रवर्तन एजेंसियों के ऊपर है कि वे बड़े डाटा विश्लेषण का प्रयोग कर संदिग्ध लेन-देन पर शिकंजा कसें।

इस दिशा में पहले ही कदम उठाये जाने शुरू हो गए हैं। 2016-17 के दौरान बैंकों द्वारा दर्ज संदेहास्पद ट्रांजेक्शन के रिपोर्टों की संख्या 2015-16 के 61,361 से बढ़कर 2016-17 में 3,61,214 हो गई है। वित्तीय संस्थाओं के लिए इसी अवधि के दौरान 40,333 से 94,836 की वृद्धि हुई है और सेबी के साथ पंजीकृत मध्यस्थों के लिए 4,579 से 16,953 की वृद्धि दर्ज की गई है।

डाटा विश्लेषण के आधार पर, आयकर विभाग द्वारा 2015-16 की तुलना में जब्त नकदी 2016-17 में दोगुनी हो गई है; विभाग द्वारा खोज और जब्ती के दौरान 15,497 करोड़ की अघोषित आय की स्वीकारोक्ति हुई है, जो 2015-16 के दौरान अघोषित आय की स्वीकारोक्ति से 38% अधिक है। 2016-17 में सर्वेक्षणों के दौरान 13,716 करोड़ रुपये की अघोषित आय की पहचान की गई है, जो 2015-16 की तुलना में 41% अधिक है।

अघोषित आय की स्वीकारोक्ति और अघोषित आय की पहचान को मिलाकर 9, 213 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई, जो संदिग्ध ट्रांजेक्शन में शामिल राशि का लगभग 18% है। जनवरी 31, 2017 को शुरू हुए 'ऑपरेशन क्लीन मनी' से इस प्रक्रिया ओ और गति मिलेगी।

मुद्रा के साथ गुमनामी को हटाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित रूप में परिणाम प्राप्त हुए हैं:

56 लाख नए व्यक्तिगत करदाताओं ने 5 अगस्त, 2017 तक अपने रिटर्न दाखिल किये, जो इस श्रेणी के लिए वापसी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी; पिछले साल यह संख्या लगभग 22 लाख थी।

गैर-कॉरपोरेट करदाताओं द्वारा 1 अप्रैल से 5 अगस्त 2017 में इसी अवधि के दौरान 2016 की तुलना में 34.25% ज्यादा स्वयं-मूल्यांकन कर (कर दाताओं द्वारा स्वैच्छिक भुगतान) का भुगतान किया गया।

कर आधार में वृद्धि और अघोषित आय को औपचारिक अर्थव्यवस्था में वापस लाने के साथ-साथ चालू वित्त वर्ष के दौरान गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं द्वारा अग्रिम कर के रूप में भुगतान की गई राशि भी 1 अप्रैल से 5 अगस्त के बीच 42% बढ़ी है।

डिमोनेटाईजेशन अवधि के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के चलते एकत्रित सुरागों से 2.97 लाख संदिग्ध शेल कंपनियों की पहचान की गई। इन कंपनियों को वैधानिक नोटिस जारी करने और कानून के तहत प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के पश्चात् 2.24 लाख कंपनियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से डि-रजिस्टर किया गया है।

इन बंद कंपनियों से बैंक खातों के संचालन को रोकने के लिए कानून के तहत और कार्रवाई भी की गई है। इनके बैंक खातों को फ्रीज करने और उनके निदेशकों को किसी भी कंपनी के बोर्ड में होने से रोकने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसी कंपनियों के बैंक खातों के शुरुआती विश्लेषण में निम्नलिखित तथ्य सामने आये हैं:

2.97 लाख बंद कंपनियों में से 28,088 कम्पनी से संबद्ध 49,910 बैंक अकाउंट्स से पता चलता है कि इन कंपनियों ने 9 नवंबर 2016 से RoC द्वारा बंद किये जाने तक 10,200 करोड़ रुपये की डिपाजिट और निकासी की है।

इनमें से कई कंपनियों के 100 से अधिक बैंक खाते हैं - एक कंपनी के पास तो 2,134 बैंक खाते हैं।

इसके साथ ही, आयकर विभाग ने 1150 से अधिक शेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसका उपयोग 22,000 से ज्यादा लाभार्थियों द्वारा 13,300 करोड़ रूपए से अधिक की राशि को व्हाईट करने के लिए एक टूल के तौर पर किया गया।

डिमोनेटाईजेशन के बाद, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों में एक ग्रेडेड सर्विलांस मेज़र अपनाया है। इस पैमाने को एक्सचेंजों द्वारा 800 से अधिक प्रतिभूतियों में शुरू किया गया है। निष्क्रिय और निलंबित कंपनियां कई बार हेराफेरी करनेवालों के लिए एक पनाहगाह के रूप में उपयोग में आती है। ऐसी 450 कंपनियों को एक्सचेंज से डिलिस्ट किया गया गया है और इनके प्रमोटरों के अकाउंट्स को भी फ्रीज किया गया है, साथ ही उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भूतपूर्व क्षेत्रीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध लगभग 800 कंपनियों का पता नहीं चल पाया है और इन्हें गायब होने वाली कंपनियों के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

डिमोनेटाईजेशन अवधि के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के चलते एकत्रित सुरागों से 2.97 लाख संदिग्ध शेल कंपनियों की पहचान की गई। इन कंपनियों को वैधानिक नोटिस जारी करने और कानून के तहत प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के पश्चात् 2.24 लाख कंपनियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से डि-रजिस्टर किया गया है।

डिमोनेटाईजेशन बचत के वित्तीयकरण में तेजी को प्रेरित करने के रूप में प्रतीत होता है। समानांतर रूप में, GST को लागू किये जाने से अर्थव्यवस्था और अधिक फॉर्मलाईजेशन की ओर शिफ्ट हुई है। बदलावों का संकेत देने वाले कुछ पैरामीटर्स निम्नलिखित हैं

कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट ने अतिरिक्त वित्तीय बचत और ब्याज दर में कमी के संचरण का लाभ देना शुरू किया है। 2016-17 में 1.78 लाख करोड़ रुपये के कॉरपोरेट बॉण्ड मार्केट जारी हुए हैं, सालाना तौर पर 78,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

पब्लिक और राइट्स इश्यूज के चलते प्राथमिक बाजार वृद्धि में आये उछाल से यह प्रवृत्ति और आगे बढ़ी है। 2015-16 के दौरान 24,054 करोड़ रुपये की इक्विटी जुटाने के लिए 87 पब्लिक और राइट्स इश्यूज थे, जबकि 2017-18 के पहले 6 महीने में ही 28,319 करोड़ रुपये के 99 ऐसे इश्यूज मौजूद हैं।

2016-17 के दौरान म्युचुअल फंडों में शुद्ध निवेश 2015-16 की तुलना में 155% बढ़ कर 3.43 लाख करोड़ तक पहुंच गया, नवंबर 2016 से जून 2017 के दौरान म्यूचुअल फंडों में शुद्ध निवेश 1.7 लाख करोड़ रुपये था, जो कि इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 9,160 करोड़ रुपये था।

लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा प्रीमियम कलेक्ट करने में नवंबर 2016 में दुगुनी वृद्धि हुई है, जनवरी 2017 के दौरान संचयी संग्रह में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रीमियम कलेक्शन में सितम्बर 2017 में इसी अवधि की तुलना में 21% की ग्रोथ देखने को मिली है।

कम नकदी अर्थव्यवस्था में बदलाव के बल पर भारत ने 2016-17 के दौरान डिजिटल भुगतान में बड़ी छलांग लगाई है। कुछ रुझान इस प्रकार हैः

करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये के 110 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिये 3.2 लाख करोड़ रुपये के और 240 करोड़ ट्रांजेक्शन किये गए। 2015-16 में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन का मूल्य क्रमशः 1.6 लाख करोड़ रुपये और 2.4 लाख करोड़ रुपये थे।

प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के साथ लेनदेन का कुल मूल्य 2015-16 में 48,800 करोड़ रुपये से 2016-17 में बढ़कर 83,800 करोड़ रुपये हो गया। पीपीआई के माध्यम से लेन-देन लगभग 75 करोड़ से बढ़कर 196 करोड़ हो गया है।

2016-17 के दौरान, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से 120 लाख करोड़ रुपये के 160 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, जबकि पिछले वर्ष 83 लाख करोड़ रुपये के लगभग 130 करोड़ के ट्रांजेक्शन हुए थे।

फॉर्मलाइजेशन के उच्च स्तर के चले उन श्रमिकों को लाभ पहुंचा है, जो ईपीएफ योगदान के रूप में सामाजिक सुरक्षा, ईएसआईसी सदस्यता सुविधाओं और बैंक एकाउंट्स में मजदूरी के डिपोजिट के लाभों से वंचित थे। श्रमिकों के लिए बैंक खातों को खोलने में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है, नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर श्रमिकों की EPF और ESIC में एनरॉलमेंट में वृद्धि हुई है। डिमोनेटाईजेशन के बाद एक करोड़ से अधिक श्रमिकों को ईपीएफ और ईएसआईसी सिस्टम से जोड़ा गया, जो कि वर्तमान लाभार्थियों की तुलना में लगभग 30% अधिक है। लगभग 50 लाख श्रमिकों के लिए बैंक खाते खोले गए, ताकि उनकी मजदूरी सीधे उनके बैंक अकाउंट में आये। इसके लिए पेमेंट ऑफ़ वेगेज एक्ट में आवश्यक संशोधन किये गए।

कश्मीर में विरोध प्रदर्शन एवं पत्थरबाजी की घटनाओं और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में नक्सल गतिविधियों में कमी को भी डिमोनेटाईजेशन के प्रभावों के तौर पर गिना जा सकता है, क्योंकि शरारती तत्वों के पास नकदी की कमी आई है। नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) तक उनकी पहुंच भी प्रतिबंधित हुई है। 2016-17 के दौरान, 1000 रुपये के एफआईसीएन का पता लगाने के लिए विमुद्रीकरण 1.43 लाख से 2.56 लाख नोटों की संख्या तक पहुंच गया। रिज़र्व बैंक की मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली में, 2015-16 के दौरान प्रत्येक मिलियन नोट की प्रोसेसिंग में 500 रुपये के एफआईसीएन के 2.4 और 1000 रुपये के एफआईसीएन के 5.8 नोट थे, जो डिमोनेटाईजेशन अवधि के बाद बढ़कर क्रमशः 5.5 और 12.4 तक पहुंच गए जो लगभग दुगुना है।

समग्र विश्लेषण में, यह कहना गलत नहीं होगा कि देश बहुत साफ़ सुथरी, पारदर्शी और ईमानदार वित्तीय व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा है। इसके लाभ अभी तक कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे सकते हैं। अगली पीढ़ी नवंबर 2016 के बाद नेशनल इकनॉमिक डेवलपमेंट को गर्व के साथ महसूस कर पायेंगे, क्योंकि डिमोनेटाईजेशन ने उन्हें रहने के लिए एक निष्पक्ष और ईमानदार व्यवस्था मुहैया करने का काम किया है। ■

(लेखक केंद्रीय वित मंत्री हैं)

प्रत्यक्ष करों के संग्रह में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि

अक्टूबर 2017 तक हुए प्रत्यक्ष करों के संग्रह के अनंतिम आंकड़ों से यह पता चलता है कि इस दौरान शुद्ध संग्रह 4.39 लाख करोड़ रुपये का हुआ है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए शुद्ध संग्रह की तुलना में 15.2 प्रतिशत अधिक है। प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रह वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल

बजट अनुमान (9.8 लाख करोड़ रुपये) का 44.8 प्रतिशत आंका गया है। अप्रैल-अक्टूबर 2017 के दौरान सकल संग्रह (रिफंड के लिए समायोजन से पहले) 10.7 प्रतिशत बढ़कर 5.28 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। अप्रैल-अक्टूबर 2017 के दौरान कुल मिलाकर 89,507 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किये गये हैं। ■

कदम जिससे अर्थव्यवस्था बदल गई

काला धन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। पहले लोगों को गुमराह करने के लिए काले धन पर सिर्फ चर्चा की जाती थी, पर उसे औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने के व्यावहारिक प्रयास कभी नहीं किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही काले धन पर करारी चोट की।

| स्मृति ईरानी |

इस सदी की शुरुआत से ही समूची दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की अलग साख बनी हुई है। वर्ष 2014 से पूर्व इस साख पर प्रश्नचिह्न लगते रहे, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा। भाजपा के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार के सत्ता में आने से पहले देश में नीतिगत पक्षाघात यानी 'पॉलिसी पैरालिसिस' की स्थिति थी। निर्णय लेने में सरकार की असमर्थता के कारण अर्थव्यवस्था की हालत जर्जर हो चुकी थी। अनेक घोटालों के कारण सरकार और देश की साख दांव पर थी। ऐसे में, जब भाजपा की सरकार आई, तो लोगों में एक नया विश्वास जगा कि अब देश में बदलाव की लहर आएगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सभी स्तरों पर भारत की छवि सुधरेगी। उनके इस विश्वास को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने शुरू से ही एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया। उनकी सोच एक पारदर्शी सरकार की स्थापना करने की थी। वे भारत को विश्व की अग्रिम पंक्ति में ले जाने के प्रति संकल्पित थे। वे निश्चय कर चुके थे कि सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़े, तो वे उससे पीछे नहीं हटेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था सुधारने की मुहिम शुरू की गई।

काला धन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। पहले लोगों को गुमराह करने के लिए काले धन पर सिर्फ चर्चा की जाती थी, पर उसे औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने के व्यावहारिक प्रयास कभी नहीं किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही काले धन पर करारी चोट की। इसको अर्थव्यवस्था में वापस लाने के लिए कई प्रयास किए, जैसे – 2014 के बजट में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन, काला धन और कर आरोपण अधिनियम, बेनामी लेन-देन निषेध (संशोधन) कानून, स्विट्जरलैंड के साथ सूचना आदान-प्रदान का करार, मॉरीशस, साइप्रस व सिंगापुर के साथ कर संधियों में परिवर्तन, दोहरा कराधान परिहार करार, धन-शोधन निवारण अधिनियम यानी मनी लॉन्डरिंग ऐक्ट आदि।

अर्थव्यवस्था के शुद्धिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आठ नवंबर, 2016 को विमुद्रीकरण का अभूतपूर्व, साहसिक और कड़ा निर्णय किया, जिसकी पूरे विश्व में सराहना की गई। विमुद्रीकरण के जरिये सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि

अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाले अवैध कार्यकलापों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और करों की चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में बैंकिंग सिस्टम में जमा किए गए काले धन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ने 31 जनवरी, 2017 को 'ऑपरेशन क्लीन मनी' की शुरुआत की। इसके तहत 17.73 लाख संदिग्ध बैंक खाताधारकों से जमा की गई राशि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। आयकर विभाग के अनुसार इस वर्ष व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या में लगभग 26.6 फीसदी का इजाफा हुआ है। यह बदलाव पारदर्शी अर्थव्यवस्था की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

विमुद्रीकरण के पश्चात 2.24 लाख से अधिक फर्जी कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया और फर्जी लेन-देन में शामिल 1150 से अधिक पंजीकृत कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई। सरकार ने बड़ी संख्या में बेनामी लेन-देन का पता लगाया है। विमुद्रीकरण का निर्णय दरअसल एक तीर से कई लक्ष्य साधने का प्रयास था। इसे लागू करने की मुख्य वजह देश की अर्थव्यवस्था के समानांतर उभरी उतनी ही शक्तिशाली काले धन की व्यवस्था को ध्वस्त करना था। यह कवायद भ्रष्टाचार, काला धन, जाली करेंसी और आतंकवादी फंडिंग को समाप्त करने के लिए सरकार के संकल्प का हिस्सा थी। काले धन पर चोट की बदौलत रियल एस्टेट में कीमतों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। विमुद्रीकरण से 'डिजिटलीकरण और कैशलेस अर्थव्यवस्था' का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। मुद्रा के ऑनलाइन आदान-प्रदान से करों की चोरी रोकने में मदद मिली है। देश के 73.63 करोड़ बैंक खाते आधार संख्या से जोड़े जा चुके हैं और इसके आधार पर प्रति माह लगभग सात करोड़ सफल भुगतान

किए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिल रहा है, जिससे बिचौलियों का तंत्र नष्ट हो गया है। विमुद्रीकरण से अब औपचारिक अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्राप्त हुई है। लोग पहले की तुलना में ज्यादा मात्रा में अपनी बचत असुरक्षित भौतिक संपत्तियों की जगह म्युचुअल फंड व जीवन बीमा जैसी योजनाओं में लगा रहे हैं। अनौपचारिक मुद्रा के औपचारिक प्रणाली में आने से अर्थव्यवस्था की तरलता में वृद्धि हुई है।

ब्याज दर में कमी के कारण निवेश की प्रक्रिया में तेजी आई है, जिससे भविष्य में अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। इससे नक्सलियों और आतंकवादियों द्वारा देश-विरोधी गतिविधियों को संचालित करने में प्रयोग की जा रही नकली मुद्रा पर भी लगाम लगी है। पत्थरबाजी और आतंकवादी प्रदर्शन जैसी घटनाएं काफी हद तक कम हुई हैं। इसी क्रम में सरकार द्वारा लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी करों की जटिलता को समाप्त कर उपभोक्ताओं को बेहतर अर्थव्यवस्था का भाग बनाने की दिशा में उठाया गया एक प्रभावशाली कदम था। अभी हाल ही में विश्व बैंक द्वारा व्यापार करने की सुगमता को ध्यान में रखकर जारी की गई सूची में भारत की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और वह पूर्व वर्षों की तुलना में लगभग 30 अंक ऊपर उठकर 100वें पायदान पर पहुंच गया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के और अधिक सुदृढ़ होने के संकेतों में से एक है।

पिछली सरकार के लंबे शासनकाल के दौरान वैश्विक स्तर पर हमारी रैंकिंग 130-140 के बीच ही बनी रही। तब कभी भी इस दिशा में प्रयास नहीं किए गए। अब पूरे विश्व में इस बात की प्रशंसा की जा रही है कि भारत बदल चुका है और एक नए भारत की नींव रखी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने दोहराया है कि अगले साल इससे भी बेहतर रैंकिंग हासिल करने के प्रयास किए जाएंगे। अगर यह कहा जाए कि विमुद्रीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में लिया गया साहसिक और सूझ-बूझ भरा फैसला था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखकर लिए जाने वाले फैसलों में तातकालिक अड़चनों व परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर नए भारत के निर्माण में इस प्रकार के फैसले लिए जाने चाहिए। ■

(लेखिका केन्द्रीय वस्त्र तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं) (हिन्दुस्तान से साभार)

सेल इस्पात से निर्मित एक्सप्रेस-वे पर वायु सेना का सुपर हरक्यूलिस विमान उतरा

भारतीय स्टील प्राधिकरण (सेल) द्वारा 33,500 मीट्रिक टन इस्पात की आपूर्ति से निर्मित आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर 24 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना के विमानों को टच एंड गो लैंडिंग की सुविधा प्रदान की गई। सेल ने इस परियोजना के लिए मुख्य रूप से भूकंप रोधी टीएमटी सरियों से बने कई उत्पादों की आपूर्ति की थी। सेल की बेहतरीन गुणवत्ता के भूकंप रोधी ईक्यूआर टीएमटी सरियें विभिन्न प्रकार के होते हैं।

भारतीय वायु सेना ने 35000 किलोग्राम भार से शुरू होने वाले सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान का एक्सप्रेस-वे पर टच एंड गो लैंडिंग का अभ्यास किया गया। एक्स्प्रेस-वे पर भारतीय वायु सेना के विमान उतारने के विशेष अभियान में पहली बार सी-130जे परिवहन विमान को शामिल किया। इससे पहले वायु सेना ने अपने मिराज-2000 और सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों को यमुना एक्सप्रेस-वे और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर उतारा था।

'सबके जीवन में थोड़ा-सा सेल है' इस टैग लाइन की भावना को ध्यान में रखते हुए कंपनी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा बाजार की जरूरतों के अनुरूप विश्व स्तरीय स्टील उत्पादों का निर्माण करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। सेल सरदार सरोवर बांध, ढोला-सादिया पुल, चेनानी-नाशरी सुरंग से लेकर विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं, बिजली संयंत्रों और गुजरात में लगने वाली एकता की प्रतिमा जैसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का अभिन्न अंग है। ■

मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ महंगाई भी काबू में

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 24 अक्टूबर को देश की अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत हुई है, बल्कि इसमें स्थिरता भी आई है। यहां प्रस्तुत है रिपोर्ट के प्रमुख अंश का प्रथम भाग:

देश का मजबूत आर्थिक विकास

2014-17 के तीन वर्षों में भारत का विकास 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की बड़ी मजबूत दर पर हुआ और 2015-16 में वृद्धि दर 8 प्रतिशत से अधिक हो गई। विमुद्रीकरण और माल एवं सेवा कर के परिवर्ती प्रभाव के कारण अंतिम दो तिमाहियों में विकास में अस्थायी मंदी आई। वह प्रभाव अब खत्म हो चुका है और सभी संकेतक-औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), केन्द्रीय क्षेत्र, सूचकांक, आटोमोबाइल, उपभोक्ताओं द्वारा किए जा रहे खर्च आदि मजबूत उछाल की ओर संकेत करते हैं और चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में ही बहुत अच्छे विकास की संभावना है।

वर्तमान वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की मुख्य विशेषता उन्नत अर्थव्यवस्थाओं एवं उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में अपेक्षाकृत सुदृढ़ आर्थिक गतिविधि के रूप में दिखाई दे रही है। वैश्विक आर्थिक गतिविधि धीरे-धीरे सुधार के मार्ग पर बढ़ रही है और वैश्विक जीडीपी वर्ष 2016 में 3.2 प्रतिशत के स्तर पर रहने के बाद वर्ष 2017 और 18 में क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की संभावना है। इस पुनरुद्धार में कारोबारी और उपभोक्ताओं के विश्वास में मजबूती के साथ-साथ निवेश, व्यापार और औद्योगिक उत्पादन में हुए उल्लेखनीय सुधार से मदद मिली है। इससे निर्यातों की वृद्धि में भी मदद मिलेगी, जो अप्रैल-सितम्बर के दौरान औसतन लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सितम्बर, 2017 में 25.6 प्रतिशत की जबरदस्त निर्यात वृद्धि में दिखाई देती है।

महंगाई पर काबू

सरकार द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों के साथ-साथ कच्चे तेल की कीमतों में 2013-14 के ऊंचे स्तरों से आई गिरावट और विक्रेय वस्तुओं की लाभकर वैश्विक कीमतों ने अर्थव्यवस्था को स्फीतिकारी चक्र से निकालकर अपेक्षाकृत स्थिर कीमतों के दौर में ला खड़ा किया है। मुद्रास्फीति 2012-13 और 2013-14 के लगभग दो अंकीय स्तर से गिरकर 5 प्रतिशत से कम की औसत पर आ गई है। जुलाई, 2016 और जुलाई, 2017 के बीच मुद्रास्फीति दर 2 प्रतिशत के आसपास थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति इस समय लगभग 4 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर है और वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इसके लगभग 3.5 प्रतिशत होने की संभावना है। इस समय मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य की परिधि के भीतर है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में इसके बढ़कर 4.2-4.6 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगा रहा है, जो 4 प्रतिशत के लक्ष्य से थोड़ा अधिक है, लेकिन 4+/-2 प्रतिशत की परिधि में है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति 2014-15 के 5.9 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में औसतन 4.9 प्रतिशत रही। 2016-17 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 4.5 प्रतिशत रही। अप्रैल-सितम्बर, 2017 में वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति 2.6 प्रतिशत थी, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुरूप अवधि में यह 5.4 प्रतिशत थी।

चालू खाता घाटा सुरक्षित परिधि में

अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति के साथ-साथ चालू खाता घाटे के कम स्तर के कारण भी पिछले तीन चार वर्षों में काफी अधिक वृहत आर्थिक स्थिरता आई है। चालू खाता घाटा 2 प्रतिशत से कम की सुरक्षित परिधि में बना हुआ है। 2011-12 और 2012-13 में चालू खाता घाटा 4 प्रतिशत से अधिक के खतरनाक और ऊंचे स्तर पर था, जिसके चलते रुपये की विनिमय दर में काफी अस्थिरता पैदा हो गई थी। चालू खाता शेष में आए उल्लेखनीय सुधार जो चालू खाता घाटे के अपेक्षाकृत कम स्तरों में दिखाई देता है, से विनिमय दर की अस्थिरता में भी काफी कमी आई है।

चालू खाता घाटा (सीएडी-कैड) 2015-16 में जीडीपी का 1.1 प्रतिशत था, जबकि 2014-15 में यह जीडीपी का 1.3 प्रतिशत था। 2016-17 में कैड और अधिक कम होकर जीडीपी का 0.7 प्रतिशत रह गया जिसकी वजह व्यापार घाटे में आया संकुचन था जो 2015-16 के 130.1 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 2016-17 में 112.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था।

भारत का जिंस व्यापार

वर्ष 2015-16 में निर्यातों में गिरावट हुई जिसकी मुख्य वजह मंद हो गई वैश्विक मांग थी और आयातों में गिरावट हुई, जिसकी वजह कच्चे

तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई तीव्र गिरावट और अन्य वस्तुओं की कीमतों में आई कमी थी। 2016-17 के दौरान निर्यातों में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आयातों में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली। अप्रैल-सितम्बर, 2017 के दौरान जिंस निर्यातों और आयातों में डालर मूल्य में क्रमशः 11.5 और 25.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा अप्रैल-सितम्बर, 2016 के 43.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-सितम्बर, 2017 में 73.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

वैश्विक व्यापार की मात्रा (माल और सेवाएं) की वृद्धि में गिरावट जारी रही और यह 2015 के 2.8 प्रतिशत से कम होती हुई 2016 में 2.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गई (आईएमएफ की डब्ल्यूईओ, अक्तूबर, 2017)। यह संभावना है कि इसमें गति आएगी और यह 2017 में 4.2 प्रतिशत और 2018 में 4.0 प्रतिशत की दर पर रहेंगे।

भारी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

2016-17 में भारत में सकल एफडीआई आगम 60.2 बिलियन अमरीकी डालर रहा, जबकि 2015-16 में यह 55.6 बिलियन अमरीकी डालर और 2014-15 में 45.1 बिलियन अमरीकी डालर रहे थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में बेहतर वैश्विक विश्वास का संकेत है। अप्रैल-अगस्त, 2017 के दौरान अर्थव्यवस्था में सकल एफडीआई आगम 30.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 23.3 बिलियन अमरीकी डालर के आगम की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक थे।

विदेशी मुद्रा भंडार

विदेशी मुद्रा भंडार मार्च- अंत 2017 में 370 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर थे, जबकि मार्च- अंत 2016 में 360.2 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर थे। 13 अक्तूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार 400 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गए। पिछले दो-एक वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार में इस वृद्धि के चलते मुद्रा भंडार पर आधारित वैदेशिक क्षेत्र के अधिकतर असुरक्षा संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है।

राजकोषीय स्थिति और राजकोषीय समेकन में सतत सुधार

पिछले कुछ वर्षों में राजकोषीय घाटे में सतत समेकन हुआ है। केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2011-12 में लगभग 6 प्रतिशत के खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गया था और 2011-12 तथा 2013-14 के बीच लगभग 5 प्रतिशत की औसत पर रहा। सरकार राजकोषीय समेकन के पथ पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसने राजकोषीय घाटे को 2016-17 में जीडीपी के 3.5 प्रतिशत तक लाने और 2017-18 में बजट अनुमानों के अनुसार इसे और कम करके 3.2 प्रतिशत तक लाने की दृढ़ता दर्शायी है।

जीडीपी के अनुपात के रूप में केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2015-16 में 3.9 प्रतिशत था और 2016-17 (संशोधित अनुमान) में 3.5 प्रतिशत था और 2017-18 में इसके 3.2 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था है। व्यय को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान देकर तथा सरकारी व्यय में व्याप्त दोषों को दूर करके और राजस्व जुटाने के नवीन प्रयासों ने यह स्थिति हासिल करने में मदद की है।

आंतरिक और वैदेशिक सरकारी ऋण स्टाक की दृष्टि से भारत को राजकोषीय शोधन क्षमता संबंधी गंभीर मुद्दों का सामना नहीं करना है। भारत सरकार का कुल बकाया देयताओं और जीडीपी अनुपात 2016-17 (सं.अ.) के अंत तक 46.7 प्रतिशत के स्तर से गिरकर 2017-18 के अंत तक 44.7 प्रतिशत हो जाने की बजटीय व्यवस्था है।

कर राजस्व (केन्द्र को निवल) में 2016-17 में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई (अनंतिम वास्तविक) और 2017-18 में इसमें 11.3 प्रतिशत की वृद्धि की बजटीय व्यवस्था है।

अप्रैल-अगस्त के दौरान राजकोषीय घाटा व्यय की फ्रंट लोडिंग के कारण पूरे वर्ष के बजटित राजकोषीय घाटे का 96 प्रतिशत है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जीडीपी के 3.2 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के पूरे वर्ष के बजटित अनुपात की सीमा लांघी नहीं जाएगी।

माल और सेवा कर (जीएसटी) के रूप में क्रांतिकारी सुधार

अनेक केन्द्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करने वाला जीएसटी एक ऐसा क्रांतिकारी सुधार है जो 1 जुलाई, 2017 से कार्यान्वित किया गया है। जीएसटी का शुभारम्भ एक ऐतिहासिक आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धि का द्योतक है, जो भारतीय कर और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में अभूतपूर्व घटना है। इसने ढांचागत सुधारों के लिए नई आशा जगाई है। इसके परिणास्वरूप देश भर में एकीकृत कर प्रणाली शुरू हुई है और इसमें माल की आवाजाही में लगी परिवहन संबंधी अड़चनों को हटाने में मदद की है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आवाजाही में तेजी आई है और एक साझा बाजार सृजित करने में, भ्रष्टाचार और हेराफेरी कम करने में तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम में और सहायता मिली है। आशा है कि इससे राजस्व, निवेश और मध्यावधिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार और जीएसटी परिषद द्वारा सुलझाई जा रही आरंभिक समस्याओं के बावजूद, जुटाए गए राजस्व के रूप में आरंभिक परिणाम उत्साहवर्धक प्रतीत होते हैं।

माल और सेवा कर: एक राष्ट्र एक कर के लाभ

- भ्रष्टाचार और हेराफेरी में कमी
- उत्पादन और बिक्री का संगठित रूप
- सहकारी राजकोषीय संघवाद

- सभी जांच चौकियां समाप्त। खपत आधारित कराधान
- अनेकानेक करों की समाप्ति। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन
- छोटे कारोबारियों और निर्यातकों पर अनुपालन के बोझ को कम करने के उपाय किए गए।

शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता

दूसरा महत्वपूर्ण सुधार शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016 (संहिता) है, जिसका लक्ष्य कंपनियों और सीमित देयतावाली संस्थाओं (सीमित देयतावाली भागीदारी और अन्य सीमित देयता वाली संस्थाओं सहित), सीमारहित देयतावाली भागीदारियों और व्यक्तियों जो विभिन्न कानूनों के तहत डील होते हैं, की शोधन अक्षमता से संबंधित कानूनों को एकीकृत करके एकल विधान में लाना है। यह संहिता वैश्विक स्तर की और कुछ मामलों में उससे भी बेहतर स्तर की समग्र, आधुनिक और सुदृढ़ शोधन अक्षमता और दिवालियापन व्यवस्था प्रदान करती है।

शोधन अक्षमता और दिवालियापन व्यवस्था

- भारत में संस्थापित एक प्रभावी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पर आधारित शोधन अक्षमता व्यवस्था।
- सुदृढ़ समयबद्ध प्रक्रिया को सुनिश्चित करने वाला त्वरित समाधान।
- जून तक एनसीटीएल के समक्ष 2050 आवेदन दायर किए गए।
- 30 सितंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के लिए 237 आवेदन स्वीकार किए गए।
- 22 स्वेच्छिक परिसमापन।
- 1054 शोधन अक्षमता कार्मिकों का पंजीकरण।
- समाधान भी प्रारंभ किया गया है।
- निधारित समयावधि में समाधान प्रक्रिया सफल नहीं होती है, तो परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
- इस चक्र को पूरा करने के लिए वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 पेश किया गया।

सरकार ने इस संहिता के कार्यान्वयन के लिए त्वरित गति से कार्रवाई की है। अभी तक एनसीएलटी को लगभग 2050 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 112 आवेदन स्वीकार किए गए हैं और 146 आवेदन खारिज किए गए अथवा वापस लिए गए हैं। स्वीकृत आवेदन के अंतर्गत कुछ लाख रुपए से लेकर कुछ हजार करोड़ रुपये की चूक अंतर्ग्रस्त है। आरबीआई द्वारा 12 बड़े चूककर्ताओं की घोषणा करने से इसका दायरा और बढ़ जाएगा। ■

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने और पुनः संरचना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने और इसे निर्णायक, प्रतिस्पर्द्धी और ग्रामीण लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं पर निर्भरता (कार्यशीलता) पर ज्यादा जोर देते हुए बेहतर निगरानी के साथ जारी रखने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। चतुर्थ वित्त आयोग (एफएफसी) अवधि 2017-18 से 2019-20 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 23,050 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गयी है। यह कार्यक्रम देश भर की सारी ग्रामीण जनसंख्या को कवर करेगा। पुनः संरचना से यह कार्यक्रम लोचदार, परिणामोन्मुख, प्रतिस्पर्द्धी बन सकेगा और इससे मंत्रालय सतत पाइप के जारिए पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा।

निर्णय के प्रमुख अंश निम्न हैं:-

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) चतुर्थ वित्त आयोग चक्र मार्च 2020 के अनुरूप जारी रखा जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) की पुनःसंरचना के फल स्वरूप जापानी एनसीफॅलाइटीस (जेई)/ एक्यूट एंसेफॅलाइटीस सिंड्रोम (एईस) प्रभावित क्षेत्रों के लिए 2 प्रतिशत धन की व्यवस्था रखी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत एक उप-कार्यक्रम अर्थात राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन, जिसे फरवरी, 2017 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, के चलते करीब 28 हजार अरसेनिक और फ्लोराड प्रभावित लोगों को (पूर्व चयनित) स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की तत्काल जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। अनुमानों के अनुसार चार वर्षों अर्थात मार्च 2021 तक करीब 12,500 करोड़ रुपए की राशि की केंद्रीय अंश के रूप में आवश्यकता होगी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत आवंटन से वित्त-पोषित किया जा रहा है। सहमति वाली योजनाओं के लिए इस राशि की दूसरी किस्त की आधी सीमा तक राज्य सरकारों द्वारा पूर्व वित्तपोषण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जिसे बाद में केंद्रीय वित्तपोषण से उनको प्रति-पूर्ति की जाएगी। यदि राज्य वित्तीय वर्ष में 30 नवंबर से पूर्व इस राशि का दावा करने में विफल रहते हैं, तो ये निधियां सामान्य पूल का हिस्सा बन जाएगी जो उच्च कार्य निष्पादक राज्यों को जारी की जाएगी जिन्होंने पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर भारत सरकार को पहले से पूर्व वित्त पोषित कर दिया है। ■

‘बच्चे नए भारत के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण हीरो’

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के दौरान कहा कि बच्चे नए भारत के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण हीरो हैं, नायक हैं। आपकी चिंता सही है कि पहले जो बीमारियां बड़ी उम्र में आती थीं, जीवन के अंतिम पड़ाव के आस-पास आती थीं - वह आजकल बच्चों में भी दिखने लगी हैं। आज बड़ा आश्चर्य होता है, जब सुनते हैं कि बच्चे भी मधुमेह से पीड़ित हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि युवा उम्र में इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त होने का एक प्रमुख कारण है - हमारी जीवन शैली में शारीरिक गतिविधि की कमी और हमारे खान-पान के तरीक़ों में बदलाव। समाज और परिवार को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रुरत है।

उन्होंने कहा कि योग, विशेष रूप से हमारे युवा मित्रों को एक स्वस्थ जीवन शैली बनाये रखने और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचाने में मददगार सिद्ध होगा। स्कूल से पहले 30 मिनट का योग, देखिए कितना लाभ देगा! घर में भी कर सकते हैं और योग की विशेषता भी तो यही है - वो सहज है, सरल है, सर्व-सुलभ है और मैं सहज है, इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी उम्र का व्यक्ति आसानी से कर सकता है। सरल इसलिए है कि आसानी से सीखा जा सकता है और सर्व-सुलभ इसलिए है कि कहीं पर भी किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक अखण्ड भारत की नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही रखी थी। भारत मां की उस महान संतान की असाधारण यात्रा से आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 31 अक्तूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गईं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेषता ये थी कि वे न सिर्फ़ परिवर्तनकारी विचार देते थे, लेकिन वे, इसको कर दिखाने के लिए जटिल-से-जटिल समस्या का व्यावहारिक हल ढूंढने में क़ाबिल थे। विचार को साकार करना, उसमें उनकी महारत थी।

श्री मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक सूत्र में पिरोने की बागडोर संभाली। ये सुनिश्चित किया कि करोड़ों भारतवासियों को ‘एक राष्ट्र और एक संविधान’ की छत्रछाया में लाया जाए। उनके निर्णय क्षमता ने उन्हें सारी बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य दिया। जहां मान-मनौवल की आवश्यकता थी, वहां उन्होंने मान-मनौवल किया; जहां बल-प्रयोग की आवश्यकता पड़ी, वहां बल-प्रयोग किया। उन्होंने एक उद्देश्य निश्चित कर लिया और फिर केवल उसी ओर पूरी दृढ़ता के साथ वो बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को एक करने का ये कार्य सिर्फ़ वही कर सकते थे, जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की जहां सभी लोग समान हों। उन्होंने कहा था और मैं चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात सदा-सर्वदा हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाली हैं। उन्होंने कहा था – “जाति और पंथ का कोई भेद हमें रोक न सके, सभी भारत के बेटे और बेटियां हैं, हम सभी को अपने देश से प्यार करना चाहिए और पारस्परिक प्रेम और सद्भावना पर अपनी नियति का निर्माण करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी, सिक्खों के पहले गुरु ही नहीं, बल्कि वो जगत-गुरु हैं। उन्होंने पूरी मानवता के कल्याण के बारे में सोचा, उन्होंने सभी जातियों को एक समान बताया। महिला सशक्तिकरण एवं नारी सम्मान पर ज़ोर दिया था। गुरु नानक देव जी ने पैदल ही 28 हज़ार किलोमीटर की यात्रा की और अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने सच्ची मानवता का सन्देश दिया। उन्होंने लोगों से संवाद किया, उन्हें सच्चाई, त्याग और कर्म-निष्ठा का मार्ग दिखाया। उन्होंने समाज में समानता का सन्देश दिया और अपने इस सन्देश को बातों से ही नहीं, अपने कर्म से करके दिखाया। उन्होंने लंगर चलाया जिससे लोगों में सेवा-भावना पैदा हुई। इकट्ठे बैठकर लंगर ग्रहण करने से लोगों में एकता और समानता का भाव जागृत हुआ।

श्री मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने सार्थक जीवन के तीन सन्देश दिए– परमात्मा का नाम जपो, मेहनत करो- काम करो और ज़रुरतमंदों की मदद करो। गुरु नानक देव जी ने अपनी बात कहने के लिए ‘गुरबाणी’ की रचना भी की। आने वाले वर्ष 2019 में, हम गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष मनाने जा रहे हैं। आइए, हम उनके सन्देश और शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ■

पत्र-पत्रिकाओं से...

नतीजे आने बाकी

सरकार का कहना है कि नोटबंदी बुनियादी रूपांतरण का एक कदम है, भारत जैसी विशाल और जटिल इकॉनमी में इसके नतीजों को जमीन पर उतरने में थोड़ा वक्त लगेगा। यह बात दुनिया भर के विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि नोटबंदी ने लेन-देन और कारोबार के चरित्र में परिवर्तन की प्रॉसेस को तेज कर दिया। इसकी वजह से न सिर्फ बैंक खातों की संख्या बढ़ी है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी चेक, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर और ई-वॉलेट के इस्तेमाल में तेजी आई है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड और पारदर्शी हुई हैं, जिससे कई तरह की गड़बड़ियां दूर हुई हैं। नोटबंदी ने पहली बार देश के आम लोगों को भी अहसास कराया कि पैसा घर में रखने की चीज नहीं, उसे बाजार में लगाए रखने में ही समझदारी है

- (नवभारत टाइम्स, 8 नवंबर)

नेक नीयत की सफलता

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि बैंकों में लौटे रुपयों से ये पता चला कि उन पर किसकी मिल्कियत है। कुल लौटे धन का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ डेढ़ लाख लोगों ने जमा कराया। जाहिर हुआ कि 18 लाख लोगों की संपत्ति उनकी आमदनी से ज्यादा है। ऐसे तमाम लोग अब आयकर विभाग की पूछताछ के दायरे में हैं। यानी नोटबंदी से काले धन पर शिकंजा कसने में सचमुच मदद मिली है। देशभर में डिजिटल लेन-देन भी बढ़ा, यह आम तजुर्बा है। इसलिए डॉ. मनमोहन सिंह के इस दावे से शायद ही कोई सहमत हो कि 'नोटबंदी संगठित और कानूनी लूट थी। इस बयान पर यदि अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री को उनके शासनकाल में हुए घोटालों की याद दिलाई, तो यह तार्किक ही है। बेहतर होता कि नोटबंदी की सालगिरह पर ऐसी सियासी तू-तू,मैं-मैं नहीं होती। इसके बदले इस फैसले के असर का वस्तुगत विश्लेषण किया जाता। इतने बड़े कदम से आम आर्थिक जिंदगी में व्यवधान नहीं पड़ता, यह संभव नहीं था। बेशक, नोटबंदी के चलते आमजन को दिक्कतें झेलनी पड़ीं, लेकिन कुल लाभ-हानि का जायजा लिया जाए, तो यही कहा जाएगा कि एनडीए सरकार ने वो निर्णय देश के व्यापक हित में लिया था। भले ही गति धीमी हो, लेकिन उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति हो रही है।

- (नई दुनिया, 8 नवंबर)

सीमित निष्कर्ष

विश्व बैंक की वर्ष 2018 की कारोबारी सुगमता संबंधी वैश्विक रैंकिंग में बहुप्रतीक्षित अच्छी खबर छिपी है। भारत 30 स्थान की उछाल के साथ अब 100वें स्थान पर आ गया है। वह उन 10 देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे ज्यादा सुधार किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए खुशखबरी है। सरकार ने इस सूचकांक के शीर्ष 50 में शामिल होने का लक्ष्य तय किया हुआ है। गत वर्ष अपेक्षाकृत धीमी शुरुआत के बाद हमने महज एक स्थान का सुधार किया था, लेकिन अब शायद सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। यह बात ध्यान देने लायक है कि ऐसे सूचकांक, खासतौर पर इस सूचकांक की चाहे जो भी सीमा हो, लेकिन वे वैश्विक निवेशकों के निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसलिए सरकार का भारत की रैंकिंग सुधारने पर ध्यान देने का निर्णय उचित है। इसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आ रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक करों का ऑनलाइन भुगतान आसान होना, किसी निर्माण अनुमति के लिए भवन योजना को पहले जमा करने की संभावना, पैन और टैन (स्थायी खाता संख्या और कर खाता संख्या) के साथ एक नया कारोबारी ढांचा और भविष्य निधि और सरकारी बीमा निस्तारण के लिए लगने वाले समय में कमी भारत के प्रदर्शन में इस सुधार की सबसे बड़ी वजह हैं।

- (बिजनेस स्टैंडर्ड, 1 नवंबर)

स्फुट विचार...

यह देश यदि पश्चिम की शक्तियों को ग्रहण करे और अपनी शक्तियों का भी विनाश नहीं होने दे, तो उसके भीतर से जिस संस्कृति का उदय होगा वह अखिल विश्व के लिए कल्याणकारिणी होगी। वास्तव में वही संस्कृति विश्व की अगली संस्कृति बनेगी।

— महर्षि अरविन्द

ऐसे बच्चे जो मुझे अपना साथ दे सकते हैं, उनके साथ अक्सर मैं हंसी-मजाक करता हूं. जब तक एक इंसान अपने अन्दर के बच्चे को बचाए रख सकता है, तभी तक जीवन उस अंधकारमयी छाया से दूर रह सकता है जो इंसान के माथे पर चिंता की रेखाएं छोड़ जाती है।

— सरदार पटेल

अब हमें समाज के इन कमजोर वर्गों में अपना आधार बनाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमें अधिक–से–अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए तथा उन्हें उस ओर समतावादी भारतीय परिवार में शामिल करना चाहिए।

— कुशाभाऊ ठाकरे

भारतीयकरण आधुनिकीकरण का विरोधी नहीं है। न भारतीयकरण एक बंधी-बंधाई परिकल्पना है। हमें भारत को एक आधुनिक राष्ट्र का रूप देना है, किंतु आधुनिकता की होड़ में हम अपनेपन को भुला न दें, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है।

— अटल बिहारी वाजपेयी

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अरुण सिंह
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1).................. (2)..................

ईमेल : ....

सदस्यता						
सदस्यता	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :.................. दिनांक :.................. बैंक : ....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

पालमपुर रैली में परंपरागत हिमाचल टोपी पहनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हिमाचल प्रदेश के पूर्व–मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल और अन्य भाजपा वरिष्ठ नेतागण

शाहपुर, कांगड़ा में आयोजित रैली में जनाभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेतागण

शाहपुर रैली (हिमाचल प्रदेश) में उपस्थित विशाल जनसमूह

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

125 करोड़ भारतवासियों ने लड़ी भ्रष्टाचार और काले धन के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी लड़ाई और... विजयी हुए !

नोटबंदी की व्यापक और ऐतिहासिक सफलता

देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा कालेधन का पर्दाफाश

देश की जनसंख्या के 0.00011% लोगों ने देश में उपलब्ध कुल कैश का 33% जमा किया

17.73 लाख संदिग्ध मामलों का पता चला

23.22 लाख खातों में लगभग 3.68 लाख करोड़ रुपये का संदिग्ध कैश जमा हुआ

6 लाख करोड़ रुपये के हाई वैल्यू नोट प्रभावी रूप से कम हुए

आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूटी

कश्मीर में पत्थरबाज़ी की घटनाएं 75% तक घट गईं

वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 20% से ज़्यादा की कमी आई

7.62 लाख जाली नोट पकड़े गए

साफ़-सुथरी अर्थव्यवस्था की ओर एक मज़बूत और दूरगामी क़दम

कालेधन में डील करने वाली शेल कंपनियों का बड़ा गोरखधंधा हुआ उजागर

शेल कंपनियों पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक, 2.24 लाख कंपनियों पर ताला लगा

नोटबंदी के बाद 35,000 शेल कंपनियों द्वारा करीब 58,000 बैंक खातों में 17,000 करोड़ रुपये जमा किए गए और निकाले गए

संगठित क्षेत्र में गरीबों के लिए बेहतर रोज़गार के अवसर बने

कर्मचारियों के पूरे वेतन का भुगतान सीधे उनके खाते में

1.01 करोड़ नए EPFO पंजीकरण हुए

1.3 करोड़ कर्मचारी ESIC में पंजीकृत- सभी को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं

नोटबंदी से टैक्सपेयर्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि

- टैक्सपेयर्स की संख्या में हुई 26.6% की बढ़ोतरी, 2015-16 में थी 66.53 लाख, 2016-17 में बढ़कर हुई 84.21 लाख
- ई-रिटर्न की संख्या में हुई 27.95% की वृद्धि, 2016-17 में 2.35 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में हुई 3.01 करोड़

लेसकैश के जरिये स्वच्छ अर्थव्यवस्था की तरफ़ भारत की बड़ी छलांग

- अगस्त 2016 में 87 करोड़ डिजिटल लेन-देन हुआ था, जबकि अगस्त 2017 में यह संख्या बढ़कर 138 करोड़ हो गई, अर्थात 58% की वृद्धि
- अब तक 15.11 लाख पीओएस मशीनें चलन में थीं, नोटबंदी के बाद सिर्फ एक साल में 13 लाख से अधिक पीओएस मशीनें इनमें और जुड़ गईं

देशवासियों को नोटबंदी से मिले ढेरों फ़ायदे, जैसे बैंक लोन पर ब्याज दरों में कमी, घर ख़रीदना हुआ सस्ता और आसान, नगरपालिकाओं की आमदनी बढ़ी आदि।

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

नोटबंदी से आपने क्या पाया?

जानने के लिए
QR कोड स्कैन करें